दैनिक लद्दाख टुडे

Title Code: LDHIN00001 | वर्षः 03 अंकः 132 | जम्मू, कश्मीर, लेह, गुरूवार 04 जून 2026 | पृष्ठः 8 | मूल्य 2 रुपए

संक्षिप्त समाचार

आतंक से जुड़े मामले में कश्मीर के 6 ज़िलों में छापे मारे गए

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) यूनिट ने घाटी के कई ज़िलों में आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में छापे मारे।

अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में मिली खुफिया जानकारी, तकनीकी विश्लेषण और लगातार की गई जांच के आधार पर उन्होंने छह ज़िलों में आठ जगहों की पहचान की थी, जहां बुधवार तड़के तलाशी अभियान चलाया गया।

यह तलाशी श्रीनगर और बांदीपोरा ज़िलों में दो–दो जगहों पर; और कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला ज़िलों में एक–एक जगह पर की गई।

2015 में दर्ज यह मामला पाकिस्तान–समर्थित आतंकी संगठनों, उनके स्लीपर–सेल नेटवर्क और जम्मू–कश्मीर में भर्ती, कट्टरपंथ फैलाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित है।

अधिकारियों ने बताया कि संदिग्धों पर आरोप है कि वे एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के संपर्क में हैं, और उन पर चरमपंथी प्रोपेगैंडा फैलाने ■ शेष पेज 2...

अनंतनाग में एनडीपीएस एक्ट के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर का 60 लाख का घर ज़ब्त

लद्दाख टूडे संवाददाता

अनंतनाग। नशीले पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, अनंतनाग पुलिस ने बुधवार को एक कथित कुख्यात ड्रग तस्कर की लगभग 60 लाख रुपये की रिहायशी संपत्ति को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट के प्रावधानों के तहत ज़ब्त कर लिया।

पुलिस ने बताया कि ज़ब्त की गई संपत्ति में छह मरला ज़मीन पर बना दो मंज़िला पक्का रिहायशी मकान शामिल है, जिसका अनुमानित बाज़ार मूल्य लगभग 60 लाख रुपये है। यह संपत्ति आसिफ हुसैन खान उर्फ सोब डॉन की है, जो अब्दुल गनी खान का बेटा और अनंतनाग के अंछिदोरा इलाके का रहने वाला है।

अधिकारियों के अनुसार, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी ■ शेष पेज 2...

मौसम

------ जम्मू ---------
अधिकतम – 32°C
न्यूनतम – 26°C
------- श्रीनगर -------
अधिकतम – 26°C
न्यूनतम – 17°C

मोदी कैबिनेट ने लिये सुपर फैसले! विमानन क्षेत्र को मिली दस हजार करोड़ की राहत

एनसीआर से पुराने ट्रक-बस हटेंगे, बिहार, तेलगाना, एमपी और ओडिशा को मिली हाईवे की सौगात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिये गये। फैसलों की जानकारी संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। बैठक में विमानन क्षेत्र को राहत देने, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने और देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया संकट के कारण विमान ईंधन की कीमतों में आई भारी अस्थिरता को देखते हुए भारतीय विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी है। इसके तहत तेल विपणन कंपनियों को अधिकतम दस हजार करोड़ रुपये तक की ब्याज मुक्त सहायता दी जाएगी। यह सहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में विमान ईंधन की कीमतें मार्च 2026 में लगभग साठ रुपये प्रति लीटर से बढ़कर मई में एक सौ बयालीस रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। विमानन कंपनियों के कुल परिचालन खर्च में ईंधन की हिस्सेदारी लगभग चालीस प्रतिशत होती है। ऐसे में यह योजना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगी। इसके तहत विमान कंपनियों को तीन वर्षों तक केवल सरकारी तेल कंपनियों से ही ईंधन खरीदना होगा। सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों पर किराये का अतिरिक्त बोझ कम होगा और छोटे शहरों तक हवाई संपर्क बना रहेगा।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के लिए लगभग नौ हजार पांच सौ पचासी करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें शामिल होंगी। योजना के अनुसार बीएस–4 या उससे पुराने मानकों वाले वाहनों को बदलकर बीएस छह अथवा विद्युत वाहनों को अपनाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार पांच वर्षों तक ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सहायता देगी, ईंधन वाउचर उपलब्ध कराएगी और वाहन खरीद पर विशेष लाभ भी दिये जाएंगे। हम आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में परिवहन क्षेत्र प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है और ■ शेष पेज 2...

विपक्ष के नेता के दावे के बाद उमर और एनसी के विधायक समीक्षा बैठक के लिए दूसरी जगह रवाना हुए

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुधवार को अपनी पार्टी के विधायकों और उन्हें समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों के साथ एक बैठक के लिए दूसरी जगह रवाना हुए। यह कदम विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के इस दावे के बीच उठाया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कभी भी गिर सकती है।

शर्मा ने दावा किया था कि सत्ताधारी पार्टी के कई विधायक पाला बदलने की कगार पर है।

अब्दुल्ला ने विधायकों की बस में सवार होकर दूसरी जगह जाते हुए तस्वीरें पोस्ट कीं; यह जगह संभवतः दाचीगाम नेशनल पार्क है।

मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर सामूहिक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, जैसे ही विधायक आवास पर पहुंचे, वे मिनी बसों में सवार हो गए और उन्हें मीडिया की नज़रों से दूर दाचीगाम ले जाया गया। अब्दुल्ला ने एक्स पर कहा, हम एक ऑफ–साइट (दूसरी जगह) के लिए रवाना हो रहे हैं, ताकि पिछले 19 महीनों का जायज़ा लेते हुए दिन बिता सकें दृ अच्छा, जो बहुत अच्छा नहीं रहा, और इनके बीच की हर बात।

एक ■ शेष पेज 2...

सीएम उमर अब्दुल्ला ने विश्व साइकिल दिवस पर साइक्लोथान को हरी झंडी दिखाई, जम्मू साइक्लोथान अभियान किया शुरू

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज यहा रायल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक साइक्लोथान को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू और कश्मीर के युवाओं के बीच फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

जम्मू और कश्मीर खेल परिषद द्वारा अपनी प्रमुख पहल माई यूथ माई प्राइड के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में घाटी के विभिन्न हिस्सों से साइकिल चालकों, युवाओं, छात्रों और खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आगामी जम्मू साइक्लो थान के लिए शुभंकर, जर्सी और प्रचार अभियान की शुरूआत ■ शेष पेज 2...

एलजी सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के होटल में आग लगने से हुई मौतों पर दुख जताया

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को दिल्ली में आग लगने की घटना में हुई मौतों पर दुख जताया।

एलजी सिन्हा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की दुखद घटना में हुई मौतों से मैं बहुत दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना ■ शेष पेज 2...

राजौरी में आतंकवाद विरोधी 'ऑपरेशन शेरूवाली' बारहवें दिन में प्रवेश कर गया

लद्दाख टूडे संवाददाता

राजौरी। भारतीय सेना, जम्मू–कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान बुधवार को राजौरी ज़िले के मंजाकोट सेक्टर में गंभीर मुग़लान और दोरीमल के घने जंगलों में अपने बारहवें दिन में प्रवेश कर गया।

सुरक्षा बल उन संदिग्ध आतंकवादियों का पता लगाने के प्रयास जारी रखे हुए है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस क्षेत्र में छिपे हुए है। सुरक्षा बलों को यात्रियों और

स्थानीय लोगों के पहचान पत्र (आईडी कार्ड) की जाँच करते हुए और क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चलाते हुए देखा गया।

'ऑपरेशन शेरूवाली' नामक यह अभियान सेना, जम्मू–कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसे विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद शुरू किया गया था, जिसमें इस क्षेत्र में संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी का संकेत मिला था।

इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संदिग्ध आतंकवादी निर्धारित क्षेत्र के भीतर ही फँसे रहें, जबकि तलाशी दल अपना अभियान जारी रखें। कठिन इलाके और घने जंगलों ने इस मिशन की जटिलता को और बढ़ा दिया है, जिसके कारण सुरक्षा बलों को लगातार निगरानी रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा है। सुरक्षा एजेंसियाँ संदिग्ध ■ शेष पेज 2...

गृह मंत्री अमित शाह 8 जून को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे

उच्च-स्तरीय बैठक में शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 जून को राष्ट्रीय राजधानी में एक उच्च–स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें जम्मू और कश्मीर में होने वाली आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा।

इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया

एजेंसियों, सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और जम्मू–कश्मीर प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है।

■ शेष पेज 2...

मुख्य सचिव ने पूरे जेएंडके में वीबी-जी राम जी को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज एक उच्च–स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें ग्रामीण विकास विभाग और जिला प्रशासनों की तैयारियों का जायजा लिया गया ताकि 1 जुलाई 2026 से पूरे जम्मू और कश्मीर में श्विकसित भारत ग्रामीण रोजगार अभियान मिशनश् को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

अधिनियम के ढांचे से नए लागू किए गए वीबी–जी राम जी में बदलाव करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। गौर तलब है कि वीबी–जी राम जी को भारत सरकार द्वारा 11 मई, 2026 को अधिसूचित किया गया था।

बारीक योजना और समन्वित ■ शेष पेज 2...

जेएंडके कांग्रेस ने महंगाई, बेरोज़गारी और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। कांग्रेस ने बुधवार को जम्मू में बढ़ती कीमतों, बेरोज़गारी और बार–बार होने वाली पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह आम लोगों को हो रही आर्थिक मुश्किलों और युवाओं की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रही है।

जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि महंगाई आम परिवारों के सामने आने वाली सबसे

बड़ी चुनौतियों में से एक बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाने–पीने की चीज़ों, कुकंग गैस, ईंधन, दवाइयों, बिजली और दूसरी ज़रूरी चीज़ों ■ शेष पेज 2...

अनियंत्रित स्कार्पियो पलटी, महिला की मौत

लद्दाख टूडे संवाददाता

उधमपुर (संजीव शर्मा)। टिकरी में एक स्कार्पियो के अनियंत्रित होकर सड़क की दूसरी ट्यूब में जाकर पलट जाने से एक महिला का मौत हो गई।

जानकारी अनुसार गत देर शाम को जम्मू से उधमपुर की ओर आ रही स्कार्पियो गाड़ी नंबर (जे.के.14,ई–8337) जैसे ही टिकरी के समीप पहुंची की चालक द्वारा गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी सड़क की अपनी लेन का पार ■ शेष पेज 2...

डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली

बेंगलुरु। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और वरिष्ठ नेता जी. परमेश्वर सहित 13 अन्य विधायकों ने उनके मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की।

एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मौजूदगी में, शिवकुमार ने संविधान की एक प्रति हाथ में लेकर संत श्गंगाधर अज्जाश के नाम पर शपथ ली।

राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने यहां लोक भवन में शिवकुमार, परमेश्वर और अन्य लोगों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। परमेश्वर, जिन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया जाना तय है, ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नाम पर शपथ ली।

शिवकुमार और परमेश्वर के साथ, जिन विधायकों ने मंत्री के तौर पर शपथ ली, वे थे कृ के. एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम. बी. पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जारकीहोली, कृष्णा बायरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, यू. टी. खादर, ईश्वर खंड्रे, यतींद्र सिद्धारमैया, बायराथी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल।

खादर और यतींद्र को छोड़कर, बाकी सभी पिछली सिद्धारमैया सरकार में मंत्री थे। खादर कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे और यतींद्र, जो विधान परिषद के सदस्य है, सिद्धारमैया के बेटे है।

64 ■ शेष पेज 2...

जेएमसी ने सफ़ाई के प्रयास तेज़ किए; अमरनाथ यात्रा के लिए आधुनिक सफ़ाई मशीनें तैनात कीं

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। जम्मू नगर निगम ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा–2026 के दौरान मुख्य सड़कों, बाज़ारों, तीर्थ यात्रा मार्गों और सार्वजनिक जगहों पर सफ़ाई बनाए रखने के लिए एक व्यापक सफ़ाई योजना बनाई है। मशीनों से होने वाली सफ़ाई के काम को मज़बूत करने के लिए, पूरे शहर में खास सफ़ाई गाड़ियों का एक बेड़ा तैनात किया गया है।

इस बेड़े में तीन छोटी

सड़क–सफ़ाई मशीनें शामिल है जो सीधे सड़क की सतह से कूड़ा, धूल और दूसरी बेकार चीज़ों को वैक्यूम से खींच लेती हैं। ये मशीनें खासकर तंग रास्तों और शहरी सड़कों की सफ़ाई में बहुत असरदार है। इसके अलावा, मुख्य सड़कों और ज़रूरी ट्रैफ़िक रास्तों की सफ़ाई के लिए इटली में बनी चार डुलेवो 6000 ■ शेष पेज 2...

Created by Universal Document Converter

शेष पेज 1 से

आतंक से जुड़े मामले ...

तथा कट्टरपंथ से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का शक है।

अनंतनाग में एनडीपीएस ...

करने के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत यह ज़ब्ती की गई। जांच में यह साबित हुआ कि यह संपत्ति कथित तौर पर अवैध ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों से जुड़ी अन्य गतिविधियों से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी।

पुलिस ने कहा कि यह कदम ड्रग व्यापार में शामिल लोगों की वित्तीय संपत्तियों और बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे एक तेज़ अभियान का हिस्सा है। अवैध तरीकों से हासिल की गई संपत्तियों को निशाना बनाकर, कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अपराधी अपने अपराध से होने वाले मुनाफे का फायदा न उठा सकें।

अनंतनाग पुलिस ने ज़िले से नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और नागरिकों से अपील की कि वे ड्रग तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करके सहयोग करें। अधिकारियों ने कहा कि नशीले पदार्थों के तस्करों और उनकी संपत्तियों के खिलाफ यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी।

मोदी कैबिनेट ने ...

केवल तीन प्रतिशत भारी वाहन ही पीएम 2.5 प्रदूषण का छत्तीस प्रतिशत हिस्सा पैदा करते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे लगभग दो लाख सात हजार वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में देश के कई राज्यों में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347–बी के 233 किलोमीटर लंबे हिस्से के उन्नयन पर चार हजार चार सौ पंद्रह करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। यह परियोजना बैतूल, खंडवा, खरगोन और बडवानी जिलों को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करेगी। इसके तहत कई बाईपास भी बनाये जाएंगे जिससे यात्रा समय कम होगा और सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा। परियोजना से वस्त्र उद्योग, मेगा फूड पार्क, ताप विद्युत संयंत्र तथा रेलवे और हवाई अड्डों को बेहतर संपर्क मिलेगा। सरकार के अनुसार इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा।

साथ ही तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्ग–63 और 563 के लगभग 191 किलोमीटर हिस्से को चार लेन में विकसित करने की मंजूरी दी गई है। सात हजार पांच सौ सत्तानवे करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से निजामाबाद, जगतियाल, मंचेरियल और करीमनगर जिलों में यातायात सुगम होगा। परियोजना पूरी होने पर यात्रा समय में डेढ़ घंटे तक की कमी आने की उम्मीद है। यह सड़क परियोजना आर्थिक और सामाजिक केंद्रों को जोड़ने के साथ–साथ माल परिवहन को भी तेज करेगी।

इसके अलावा, बिहार में खगडिया से पूर्णिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग–31 और 231 के एक सौ तैंतालीस किलोमीटर हिस्से को चार लेन बनाने की परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। करीब तीन हजार नौ सौ छत्तीस करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जिलों को लाभ पहुंचाएगी। परियोजना के तहत पूर्णिया शहर के लिए ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनाया जाएगा। इससे यात्रा समय घटकर लगभग दो घंटे रह जाएगा और माल परिवहन अधिक सुगम होगा।

इसके अलावा ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक नए तटीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी गई है। लगभग आठ हजार तीन सौ करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत एक सौ साठ किलोमीटर लंबी सड़क विकसित की जाएगी। इससे पुरी, केंद्रापाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों को बेहतर संपर्क मिलेगा और यात्रा समय में ढाई घंटे तक की कमी आएगी। परियोजना से पर्यटन, मत्स्य उद्योग और बंदरगाह गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन सभी सड़क परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और देश की लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूती मिलेगी।

विपक्ष के नेता के दावे ...

अन्य पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक को आखिरी समय में दूसरी जगह नहीं ले जाया गया, बल्कि यह एक पहले से तय योजना थी। उन्होंने कहा, मुझे आपको निराश करने का खेद है, लेकिन इसे आखिरी समय में दूसरी जगह नहीं ले जाया गया है। मेरा इरादा हमेशा से इस बैठक को दूसरी जगह आयोजित करने का था, और जिस जगह को मैंने मूल रूप से चुना था, वहां सभी इंतज़ाम कई दिन पहले ही कर लिए गए थे।

पार्टी के एक नेता ने बताया कि विधायकों और कुछ सांसदों को दाचीगाम नेशनल पार्क ले जाया गया है। अब्दुल्ला ने रविवार को विधायकों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में कहा था कि बैठक में सामूहिक महत्व के मामलों और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और विचार–विमर्श किया जाएगा।

अपनी पार्टी के विधायकों के अलावा, अब्दुल्ला ने उन चार निर्दलीय विधायकों को भी आमंत्रित किया था जो उनकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं।

एलजी सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने ...

करता हूं। बुधवार को दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की एक संकरी गली में स्थित एक होटल में भीषण आग लग गई जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे जिनके बीमार रिश्तेदारों का इलाज पास के अस्पतालों में चल रहा था। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने भी इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया।

सीएम उमर अब्दुल्ला ने विश्व ...

की और इस कार्यक्रम की तारीखों की घोषणा की। उन्होंने कश्मीर साइ क्लोथान को एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने की भी घोषणा की जिसका उद्देश्य पूरे देश से साइकिल चालकों को आकर्षित करना और जम्मू और कश्मीर को साहसिक और खेल गतिविधियों के केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है।

प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने साइकिल चलाने में बढ़ती रुचि की सराहना की और बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय जीवन शैली अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने साइकिल चलाने को परिवहन के एक पर्यावरण–अनुकूल साधन के रूप में रेखांकित किया जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान देने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का भी समर्थन करता है। मुख्यमंत्री ने खेल और मनोरंजक गतिविधियों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए युवा सेवा और खेल विभाग तथा जम्मू और कश्मीर खेल परिषद द्वारा की जा रही पहलों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल फिटनेस को बढ़ावा देते हैं बल्कि सामुदायिक जुड़ाव को भी मजबूत करते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं।

इस साइक्लोथान ने युवाओं के बीच निष्क्रिय जीवन शैली, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताने की आदतों से लड़ने का संदेश दिया साथ ही फिटनेस और खेल की भावना को भी बढ़ावा दिया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था–नशीली दवाओं को ना, स्क्रीन की लत को ना और फिटनेस व खेल को हां। इस अवसर पर युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, युवा सेवा और खेल विभाग के आयुक्त सचिव शाहिद इकबाल चौधरी, आरएसजीसी के सचिव हारिस अहमद हांडू, जम्मू और कश्मीर खेल परिषद की सचिव नुजहत गुल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। साइकिलिंग जागरूकता रैली आरएसजीसी से शुरू हुई और फोरशोर रोड पर स्थित डक पार्क की ओर आगे बढ़ी जिसने लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय की। इस कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्गों के बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जो शहर के निर्धारित मार्गों से होकर गुजरा।

गृह मंत्री अमित शाह ...

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री इस वार्षिक तीर्थयात्रा में शामिल सुरक्षा और नागरिक विभागों की तैयारियों का मूल्यांकन करेंगे, और यात्रा के सुचारू, सुरक्षित और सफल संचालन को सुनिश्चित करने के उपायों की समीक्षा करेंगे।

चर्चा का मुख्य केंद्र पारंपरिक पहलगाम और बालटाल मार्गों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, आतंकवाद–रोधी रणनीतियाँ, तीर्थयात्रियों के काफिलों की सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ, संचार प्रणालियाँ और समग्र रसद व्यवस्थाएँ होने की संभावना है।

अधिकारियों से यह भी उम्मीद है कि वे गृह मंत्री को जम्मू और कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा स्थिति और यात्रा की पूरी अवधि के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देंगे।

विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया समन्वय, यात्रा मार्गों पर निगरानी के उपाय, और किसी भी अप्रत्याशित चुनौती या सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है।

यह समीक्षा बैठक केंद्र की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा में शामिल होने की उम्मीद रखने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और कुशल सुविधाओं को सुनिश्चित करना है।

अनियंत्रित स्कार्पियो ..

करते हुए दूसरी ट्यूब में घुस गई तथा पलट गई, जिससे उसमें सवार एक महिला जिसकी पहचान गीता देवी निवासी विलावर जोकि इस समय गैंडा तालाब के समीप किराये के मकान में रह रही थी, के रूप में की गई है, गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत टिकरी अस्पताल में पहुंचाया गया, यहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु जीएमसी में पहुंचाया, यहां पर शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

जेएमसी ने सफ़ाई के ...

सड़क–सफ़ाई गाड़ियां तैनात की गई हैं। सड़कों के किनारे और दूसरी सार्वजनिक जगहों से जमा कूड़ा और मलबा उठाने के लिए, ज़ोरदार वैक्यूम सक्शन सिस्टम वाली दो जीवीपी गाड़ियां भी सेवा में लगाई गई हैं।

ये सभी गाड़ियां मुख्य रूप से रात के समय चलती हैं, जब ट्रैफ़िक बहुत कम होता है। क्योंकि मशीनों से सफ़ाई करने वाली गाड़ियां सफ़ाई करते समय काफ़ी धीमी गति से चलती हैं, इसलिए रात में इन्हें तैनात करने से वे यात्रियों की आवाजाही में रुकावट डाले बिना सड़कों को ज़्यादा अच्छे और सुरक्षित तरीके से साफ़ कर पाती हैं। ज़रूरी रखरखाव और मरम्मत के बाद इन मशीनों को फिर से चालू करने से, पूरे शहर में सफ़ाई के स्तर में काफ़ी सुधार होने की उम्मीद है।

मशीनों से सफ़ाई करने वाले बेड़े के बारे में जानकारी देते हुए, जम्मू नगर निगम के मुख्य परिवहन अधिकारी (ज़ोन ॅॅ) बलकार अंगुराना ने बताया कि इन गाड़ियों को इस तरह से तैनात किया गया है ताकि उनकी असरदारता ज़्यादा से ज़्यादा हो और सफ़ाई के बेहतर नतीजे मिलें। उन्होंने बताया कि तीन छोटी सड़क–सफ़ाई मशीनें सीधे सड़क की सतह से धूल और कूड़ा वैक्यूम से खींचने में सक्षम हैं, जबकि डुलेवो 6000 और जीवीपी गाड़ियों का इस्तेमाल बड़ी सड़कों और सार्वजनिक जगहों की सफ़ाई के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सभी मशीनें रात के समय चलाई जा रही हैं ताकि काम आसानी से हो सके और ट्रैफ़िक से कम से कम रुकावट के साथ सड़कों की पूरी सफ़ाई हो सके।

मशीनों से सफ़ाई के अलावा, निगम नियमित सफ़ाई गतिविधियां भी जारी रखे हुए है, जिसमें घर–घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना, हाथों से सफ़ाई करना, नालियों की सफ़ाई और लोगों में जागरूकता फैलाने के अभियान शामिल हैं। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे इधर–उधर कूड़ा न फेंककर और कूड़े को सिर्फ़ तय जगहों पर ही डालकर सहयोग करें।

राजौरी में आतंकवाद ...

आतंकवादियों की गतिविधियों पर नज़र रखने और इस क्षेत्र में उनकी मौजूदगी से उत्पन्न किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग कर रही हैं।

पूरा क्षेत्र कड़ी सुरक्षा घेरे में है, और कुछ स्थानों तक पहुँच पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता और सुरक्षा से जुड़ी सभी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता।

मुख्य सचिव ने पूरे ...

निष्पादन के महत्व पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस योजना को चालू करने के लिए निर्धारित समय–सीमाओं का कड़ाई से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि 1 जुलाई, 2026 को इसके शुरू होने से काफी पहले ही सभी प्रारंभिक गतिविधियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने सभी आवश्यक पूर्व–शर्तों को तेजी से पूरा करने का आह्वान किया।

इनमें विधि विभाग के परामर्श से योजना की अधिसूचना जारी करना, सभी पात्र श्रमिकों का ई–केवाईसी पूरा करना और नए ढांचे में सुचारू तथा निर्बाध बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यों की अग्रिम योजना बनाना और उन्हें मंजूरी देना शामिल है। मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास, जम्मू और कश्मीर के निदेशकों को यह भी निर्देश दिया कि वे इस योजना के कार्यान्वयन से जुड़े सभी पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिला, ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को वीबी–जी राम जी के लागू होने से पहले इसके प्रावधानों, प्रक्रियाओं और तकनीकी मंचों के बारे में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और पूरी तरह से अवगत होना चाहिए।

बैठक के दौरान ग्रामीण विकास सचिव एजाज असद ने जानकारी दी कि सभी जिलों में व्यापक जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों के तहत विशेष ग्राम सभाओं, सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रमों, सोशल मीडिया अभियानों और समाचार पत्रों के माध्यम से जनसंपर्क पहलों के जरिए सभी 4,291 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया है।

जेएंडके कांग्रेस ने ...

की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से घरों का बजट बुरी तरह प्रभावित हुआ है, और इसका सबसे ज़्यादा असर आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों पर पड़ रहा है।

भल्ला ने आरोप लगाया कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्टेशन की लागत पर भी पड़ा है, जिससे अनाज, सब्ज़ियों और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दूसरी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ गई हैं।

उन्होंने सरकार से कीमतों को स्थिर करने और समाज के कमज़ोर तबकों को राहत देने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की।

उन्होंने महंगाई से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की मांग की, और रोज़गार पैदा करने, उत्पादक क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश करने और घरों की आय बढ़ाने तथा आर्थिक विश्वास बहाल करने के लिए मज़बूत सामाजिक कल्याण योजनाओं की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

पूर्व मंत्री योगेश साहनी ने कहा कि यह प्रदर्शन उन नागरिकों में बढ़ रही निराशा को दिखाता है जो बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साहनी ने कहा कि कांग्रेस तब तक प्रदर्शनों और संस्थागत मंचों के ज़रिए जनता के मुद्दे उठाती रहेगी, जब तक कि राहत के ठोस उपायों की घोषणा नहीं हो जाती।

जेकेपीसीसी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि बढ़ती कीमतों से ग्राहकों की मांग कम हुई है, कारोबार प्रभावित हुए हैं और युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सीमित हो गए हैं।

डी.के. शिवकुमार ने ...

वर्षीय वोक्कालिगा समुदाय के कद्दावर नेता शिवकुमार को 28 मई को मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद, 30 मई को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था। शिवकुमार सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके थे।

शपथ ग्रहण समारोह में एआईसीसी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कई शीर्ष नेता, गणमान्य व्यक्ति और आमंत्रित मेहमान मौजूद थे। विभिन्न मठों के प्रमुखों सहित सभी प्रमुख समुदायों के धार्मिक नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अधिकारियों के अनुसार, आमंत्रित मेहमानों में कनकपुरा के डोड्डालाहल्ली स्थित एक सरकारी स्कूल के छात्र भी शामिल थे; डोड्डालाहल्ली शिवकुमार का पैतृक गांव है। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, जिनमें मज़दूर, नागरिक कर्मचारी, किसान नेता, महिला स्वयं–सहायता समूह और कन्नड़–समर्थक संगठन शामिल थे।

HELPLINE

POLICE STATIONS	
Bagh-e-Bahu	2459777
Bakshi Nagar	2580102
Bus Stand	2575151
City	2543688
Gandhi Nagar	2430528
Gangyal	2482019
Nowbad	2571332
Pacca Danga	2548610
Railway Station	2472870
Sainik Colony	2462212
Satwari	2430364
Channi Himmat	2465164
Transport Nagar	2475444
Trikuta Nagar	2475133
Gandhi Nagar	2459660
SSP City	2561578
SP City North	2547038
SP South	2433778
Public Utility Services	
INDIAN AIR LINES	
City Office	2542735
Air Port	2430449
Jet Air Ways	2453999
City Office	2573399
RAILWAYS	
Railway Enquiry	131, 132, 2476407
Booking	2470318
Reservation	2470315
Public Health Engineering Stations	
Bakshi Nagar	2543557
Gandhi Nagar	2430786
Company Bagh	2542582
New Plot	2573429
Panjtirthi	2547537
Telecommunication Department	
Directory Enquiry	197
Fault Repair	198
Trunk Booking	180
Billing Complaint	2543896
JAMMU MUNICIPALITY	
Jn. Lines	2578503
Administration Officer	2542192
Health Officer	2547440
POSTAL SERVICES	
Head Post Office City	2543606
Gandhi Nagar	2435863
FIRE SERVICES	
Control Room	101, 132, 2476407
City	2544263
Gandhi Nagar	2457705
Canal	2554064
Gangyal	2480026
COOKING GAS DEALERS	
Chenab Gas	2547633
Gulmour Gas	2430835
JAKFED	2548297
HP Gas	2578456
Shivangi Gas	2577020
Tawi Gas	2548455
POWER HOUSES	
Gandhi Nagar	2430180
Canal Road	2554147
Janipur	2533828
Nanak Nagar	2430776
Parade	2542289
Satwari Cantt.	2452813
HOSPITALS	
GMC Hospital	2584290
S.M.G.S. Hospital	2547635
C.D. Hospital	2577064
Dental Hospital	2544670
Gandhi Nagar Hospital	2430041
Sarwal Hospital	2579402
G.B. Pant Cantt. Hospital	2433500
Ayurvedic College	2543661
C.R.P. Hospital	2591105
Acharya Shri Chander	2662536
Mental Hospital	2577444
Swami Vivekanand	2547418
Blood Bank	2547637
Ambulances	2584225, 2575364
Ambulances (Red Cross)	2543739
NURSING HOMES	
Maddan Hospital	2456727
Medicare	2435070
Triveni Nursing Home	2452664
Suvidha Nursing Home	2555965
Al. Firdous Nursing Home	2545050
Astha Nursing Home	2576707
Bee Enn Charitable Trust	2505310
Chopra Nursing Home	2573580
Harbans Singh Mem Hsp.	2541952
Jeevan Jyoti	2576985
Yudhvir Nursing Home	2547821
Mediaid Nursing Home	2466744
Sita Nursing Home	2435007
Vibhuti Nursing Home	2547969
Rameshwar Nursing Home	2580601
Bee Enn Cheritable	2555631
Maharishi Dayanand	2545225

Created by Universal Document Converter

बस 1 प्रतिशत काम बाकी... भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर बोले-समझौते के बेहद करीब

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। भारत में अमेरिका के राज. दूत सर्जियो गोर ने बुधवार कहा कि ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सभी बड़े मतभेद सुलझ गए है। सर्जियो गोर ने कहा कि 99 फीसदी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और केवल एक प्रतिशत काम बाकी है। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ ही हफ्तों में समझौता हो जाएगा। सर्जियो गोर ने कहा कि यह डील भारत और अमे. रिका दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होगी।

7 फरवरी को भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी कर द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की रूपरेखा तय की थी। अब दोनों पक्षों को उस रूपरेखा को कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज में बदलना है। सर्जियो गोर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बातचीत की प्रगति अच्छी है।

वहीं वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत अमेरिका के साथ धारा 301 के तहत की गई कार्यवाही और दोनों देशों के बीच हुए अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए लगातार बातचीत जारी है। भारत सरकार बंधुआ मजदूरी और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता के मुद्दों पर धारा–301 से जुड़ी जांच के संबंध में अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है।

सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए यह भी बताया कि वह अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भी अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है। अमेरिकी व्यापार प्रति. निधि (यूएसटीआर) के कार्यालय ने 11–12 मार्च 2026 को बंधुआ मजदूरी और अति. रिक्त औद्योगिक क्षमता से जुड़े मुद्दों पर 60 देशों के खिलाफ धारा–301 के तहत जांच शुरू की थी।सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए यह भी बताया कि वह अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भी अमेरिका के साथ बात. चीत कर रही है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के कार्यालय ने 11–12 मार्च 2026 को बंधुआ मजदूरी और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता से जुड़े मुद्दों पर 60 देशों के खिलाफ धारा–301 के तहत जांच शुरू की थी।

यूएसटीआर ने दो जून को बंधुआ मजदूरी से जुड़ी जांच के निष्कर्ष जारी करते हुए 60 देशों से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मैक्सिको और पाकिस्तान से आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क जबकि भारत तथा चीन सहित 54 अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर 12.5 प्रतिशत शुल्क शामिल है।

मन अत्यंत व्यथित है, मालवीय नगर अग्निकांड पर पीएम मोदी और अमित शाह ने जताया गहरा दुख

नई दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसे को लेकर पूरे देश में दुख की लहर है।

इसी बीच पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मालवीय नगर अग्निकांड पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश जारी कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम ने राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान भी किया है। साथ ही, गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मालवीय नगर में हुए अग्निकांड पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया कि इस हादसे में लोगों की मौत बेहद दुखद है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की।

उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद पहुंचा रहा है। साथ ही पीएम राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से हादसे में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है।

अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि मालवीय नगर में आग लगने की घटना से उनका मन अत्यंत व्यथित है। उन्होंने कहा कि इस हृदयविदारक हादसे में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं है। गृह मंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि शोकाकुल परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले।

गृह मंत्री ने अपने बयान में घायलों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि घायलों को जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और वह सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस , दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, कैट्स एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों को तत्काल मौके पर भेजा गया। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है।

बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल दोहराने की तैयारी! टीएमसी में बड़ी बगावत, ममता बनर्जी के सामने अस्तित्व का संकट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी अजेय दिखने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) आज अपने अस्तित्व के सबसे गंभीर आंतरिक संकट से जूझती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शुरू हुआ असंतोष अब खुले शक्ति संघर्ष में बदलता दिखाई दे रहा है। पार्टी से निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी का यह दावा कि विधानसभा अध्यक्ष ने बागी खेमे को अलग विधायी दल के रूप में मान्यता दे दी है, ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा उस संख्या की हो रही है जो टीएमसी के भविष्य का फैसला कर सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी के कुल 80 विधायक है और दल–बदल विरोधी कानून के तहत किसी समूह को वैध रूप से अलग पहचान हासिल करने के लिए कम से कम 54 विधायकों का समर्थन चाहिए। बागी खेमे का दावा है कि उसके साथ 60 विधायक हैं। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह केवल बगावत नहीं बल्कि टीएमसी के भीतर सत्ता संतुलन बदलने वाली घटना हो सकती है।

चुनावी हार के बाद किसी भी राजनीतिक दल में आत्ममंथन और असंतोष स्वाभाविक होता है, लेकिन टीएमसी में यह असंतोष संगठनात्मक चुनौती में बदलता दिख रहा है। एक दशक से अधिक समय तक बंगाल की राजनीति पर एकछत्र प्रभाव रखने वाली पार्टी पहली बार ऐसी स्थिति में पहुंची है जहां उसके अपने विधायक

नेतृत्व के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे है।

ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा मजबूत केंद्रीय नेतृत्व पर आधारित रही है। पार्टी के भीतर बड़े फैसले शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर होते रहे है। लेकिन सत्ता कमजोर पड़ने के साथ ही संगठन के भीतर दबे हुए मतभेद सतह पर आने लगे है। कई नेताओं और विधायकों को लगता है कि चुनावी हार के कारणों पर गंभीर समीक्षा के बजाय जिम्मेदारी तय करने से बचा गया।

संकट को और गहरा करने वाला मुद्दा कथित फर्जी हस्ताक्षर विवाद है। शुरू में यह मामला विधायकों के समर्थन पत्रों की वैधता तक सीमित था, लेकिन जल्द ही यह राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया। मामले की जांच शुरू होने के बाद कई विधायकों के बयान दर्ज किए गए और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक सवाल पहुंच गए।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि हस्ताक्षरों को लेकर विवाद असल समस्या नहीं है, बल्कि यह पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रहे अविश्वास और गुटबाजी का परिणाम है। चुनावी हार ने उन अंतर्विरोधों को उजागर कर दिया है जिन्हें अब तक सत्ता की मजबूती ढंककर रखे हुए थी।

टीएमसी के भीतर पैदा हुए हालात की तुलना 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना के विभाजन से की जा रही है। उस समय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया था और अंततः पार्टी का नियंत्रण ही बदल गया था।

बंगाल में भी चर्चा इसी बात की है कि यदि 54 या उससे अधिक विधायक बागी खेमे के साथ है तो दल–बदल विरोधी कानून उनके खिलाफ प्रभावी नहीं रहेगा। यही वजह है कि 60 विधायकों के समर्थन का दावा राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि दोनों परिस्थितियों में फर्क भी है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का सवाल था, जबकि बंगाल में मामला विपक्ष के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक नियंत्रण का है। फिर भी संख्या बल की राजनीति दोनों मामलों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इस पूरे संकट के बीच सबसे ज्यादा दबाव ममता बनर्जी के बाद पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी पर दिखाई दे रहा है। लंबे समय से उन्हें ममता के राजनीतिक उत्तरा. धिकारी के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन हालिया विवादों और जांच प्रक्रियाओं ने उनकी राजनीतिक स्थिति को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पार्टी के भीतर एक वर्ग मानता है कि नेतृत्व के केंद्रीकरण और कुछ चुनिंदा नेताओं पर अत्यधिक निर्भरता ने संगठनात्मक असंतोष को बढ़ाया। यही असंतोष अब राजनीतिक चुनौती का रूप लेता दिखाई दे रहा है।

पकड़ा गया होटल मालिक लवकेश बजाज, दिल्ली पुलिस ने शुरू की पूछताछ

नई दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में हुए अग्निकांड के मामले में पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हादसे के बाद लवकेश बजाज और उसके दो पार्टनर्स को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।लवकेश बजाज के घर पर भी दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची थी। इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस को यह भी शक था कि इस अग्निकांड के बाद कार्रवाई से बचने के लिए लवकेश बजाज विदेश भी भाग सकता है,

सिंगल एंट्री-एग्जिट, 6 की जगह 25 कमरे, दिल्ली का होटल 21 लोगों के लिए कैसे बन गया काल?

नई दिल्ली। दिल्ली में हुए अग्निकांड में सिर्फ राजधानी के लोगों ने अपनी जान नहीं गवाई, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के सुदूर कांगो देश से अपने एक रिश्तेदार का इलाज कराने दिल्ली आई एक युवती भी दुर्घटना का शिकार बन गई। मृतक महिला की बहन ने रोते हुए बताया कि रेस्टोरेंट में लगी आग ने उसकी बहन को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। ये तो सिर्फ एक परिवार की कहानी है। ऐसे न जाने कितने परिवारों ने अपने प्रियजनों को इस हादसे में खो दिया। अब तक 21 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। सवाल वही है, जो इस तरह के हर हादसे के बाद होता है कि लापरवाही की भेंट चढ़ी इन 21 जिंदगियों का जिम्मेदार कौन है?

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस रेस्टोरेंट में आग लगी, उस

बिल्डिंग में ही एक होटल में अवैध कमरे चल रहे थे। इस होटल को सिर्फ 6 कमरों की अनुमति मिली हुई थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर पूरे 25 कमरों का होटल चलाया जा रहा था। फायर और सेफ्टी विभाग से एनओसी भी नहीं ली गई थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े होटल में जाने और वहां से लौटने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। इस हादसे में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग अफ्रीका या मध्य एशिया के है।

घटनास्थल से 40 से ज्यादा घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब तक 21 लोगों की मौत जरूर हुई है, लेकिन घायलों की हालत देखने अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। जिस होटल और रेस्टोरेंट में यह हादसा हुआ वह हौज रानी इलाके में स्थित श्फ्लोरिश स्टे बीएंडबीश के नाम से जाना जाता है। इसमें सुबह करीब 8. 45 बजे आग लगी थी।

इस हादसे ने नियमों के पाल की कमियों को उजागर किया है। होटल अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मेहमानों को हैंडल कर रहा था और खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और शुरुआती जांच के नतीजों से पता चलता है कि कई पीड़ितों की मौत दम घुटने से हुई, खासकर उन लोगों की जो बेसमेंट वाले हिस्से में फंस गए थे। इंडिया टुडे के अनुसार, बेसमेंट में अवैध कमरे चलाए जा रहे थे।

जांच में यह भी पता चला है कि इस प्रॉपर्टी को श्बेड एंड ब्रेकफास्टश कैटेगरी के तहत सिर्फ छह कमरों की अनुमति मिली थी, लेकिन इंडिया टुडे के अनुसार लगभग 25 कमरे चला रही थी। इस इमारत में एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पांच ऊपरी मंजिलें हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी, हालांकि आग लगने के सही कारण की अभी भी जांच चल रही है।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार होटल में आने–जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ श्गैर–इरादतन हत्याश का केस दर्ज कर लिया है। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या होटल में आग से बचाव के लिए जरूरी उपकरण मौजूद थे।

नेपाल के पीएम बालेन शाह को नसीहत! पीएम मोदी से मिलकर बोले रबी लामिछाने- मैं आपके विजन में सहभागी हूं

नई दिल्ली। नेपाल के सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक घंटे मुलाकात की और सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया। लामिछाने मंगलवार को ही भारत आए और उनकी पीएम मोदी से मुलाकात भारत और नेपाल के संबंधों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कड़ी है। इससे पहले उनकी गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात हो चुकी है, जो कि नेपाल के नए–नवेले प्रधानमंत्री बालेन शाह के लिए बहुत बड़ी नसीहत की तरह है।

नेपाली सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े नेता रबी लामिछाने से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट करके

इसकी तस्वीरें साझा कीं और लिखा, श्नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष श्री रबी लामिछाने से मिलने का अवसर मिला, इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। एक साझा और समृद्ध भविष्य के लिए साथ मिलकर कार्य करने की आपकी आकांक्षा का मै स्वागत करता हू और इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं।श

पीएम मोदी के इस पोस्ट के जवाब में रबी लामिछाने ने जो जवाब दिया है, उससे लगता है कि उन्हें जरा भी यकीन नही रहा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री से उन्हें इतना सम्मान मिलेगा। उन्होंने लिखा है, श्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज एक घंटे तक इतनी सार्थक चर्चा करना सचमुच बहुत ही सुखद रहा।श

उन्होंने लिखा है, श्हमारी साझा समृद्धि को लेकर नेपाल और भारत के लोगों के लिए आरएसपी इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलते देखने को उत्सुक है। रबी लामिछाने, अध्यक्ष,राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी,नेपालश

रबी लामिछाने नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह के सत्ताधारी दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की कमान संभाल रहे है। वह भारत आकर सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनी. तिक पार्टी होने का दावा करती है।

नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़ से कम है, जबकि बीजेपी के दावे के मुताबिक उसके 14 करोड़ से ज्यादा सदस्य है। नितिन नवीन के बाद लामिछाने ने मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह और जयशंकर से भी मुलाकात की और हर जगह उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ।

ईरान द्वारा कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक में भारतीय की मौत 63 घायलों को अस्पताल ले जाया गया, तनाव

कुवैत। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। कुवैत स्थित भारत के दूतावास ने इसकी पुष्टि कर दी है। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हमले में 63 लोग घायल हुए है, जिनमें हवाई अड्डे के कर्मचारी और यात्री शामिल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले में हवाई अड्डे की सुविधाओं और राजनयिक मिशनों को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है।

इंडियन एंबेसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, श्कुवैत स्थित भारतीय दूतावास आज कुवैत के हवाई अड्डे पर हमले में एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास मृतक के परिवार के संपर्क में है और कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर मृतक के परिवार और घटना में घायल हुए लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए समन्वय स्थापित किए हुए है।

कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से उनकी जमीन पर क्रूर हमले किए है। ईरान के इस तरह के हमले क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। बयान के अनुसार, इन हमले में कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित कई नागरिक और महत्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं को निशाना बनाया गया। कुवैती विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह ईरान के इन हमलों को पूरी तरह खारिज करता है। इस तरह की घटनाएं ना केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाती है बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और 2026 के सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2817 का भी उल्लंघन है। कुवैत की संप्रभुता, सुरक्षा और उसके नागरिकों की रक्षा रेड लाइन है, जिसे किसी भी हालत में पार नहीं किया जा सकता।

वागूरा पंचायत ने जीता राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025

पूरे भारत की 2.5 लाख पंचायतों में तीसरा स्थान हासिल किया

नई दिल्ली। ग्रामीण जम्मू–कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर, बडगाम जिले की वागूरा ग्राम पंचायत ने प्रतिष्ठित श्दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारश (डीडीयूपीएसवीपी) 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है, और इसके साथ ही 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी जीता है।

यह पुरस्कार, जो ष्सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामा. जिक रूप से सुरक्षित पंचायतष श्रेणी के तहत दिया जाता है, नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने जम्मू–कश्मीर के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को यह सम्मान सौंपा।

यह सम्मान समावेशी शासन, सामाजिक न्याय और सतत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वागूरा के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है। ग्राम पंचायत ने एक कठोर राष्ट्रीय–स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद यह जीत हासिल की, जिसमें देश भर की हजारों पंचायतों ने हिस्सा लिया था।

अधिकारियों ने इस उपलब्धि का श्रेय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार के दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव मोहम्मद एजाज असद के निरंतर मार्गदर्शन को दिया।

एजाज असद के नेतृत्व में, विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर शासन–प्रशासन को बेहतर बनाने और कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित रणनीति अपनाई। नियमित समीक्षाएं, पंचायतों को निरंतर सहयोग (हैंडहोल्डिंग) और लगातार निगरानीकृये सभी कारक वागूरा को यह राष्ट्रीय गौरव हासिल कराने में निर्णायक साबित हुए।

यह पुरस्कार जम्मू–कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने में पंचायती राज संस्थाओं, निर्वाचित प्रति. निधियों, स्थानीय समुदायों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों को दर्शाता है।

300 जहाजों ने होर्मुज से निकलने का परमिट मांगा 77 प्रतिशत भारत-चीन आने वाले, ईरान की नई टोल संस्था का दावा

तेहरान। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में टोल सिस्टम लागू कर दिया है और दुनियाभर के जहाज परमिट के लिए अप्लाई कर रहे है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अब तक 300 से ज्यादा जहाजों ने होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान की संबंधित अथॉरिटी से आवे. दन किया है। ईरानी सरकार की नई टोल संस्था पीजीसीए इस महत्वपूर्ण मार्ग पर एक स्थायी टोल प्रणाली स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है।

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण (पीजीएसए) ने बताया है कि होर्मुज से सुरक्षित रास्ता मांगने के लिए आवेदन करने वाले ज्यादातर जहाज तेल टैंकर है। इनमें करीब 77 प्रतिशत आवेदक फारस की खाड़ी से निकलकर एशिया आने वाले है। एशिया में भी ज्यादातर जहाज चीन और भारत आना चाहते थे। चीन और भारत खाड़ी देशों के ईंधन के सबसे बड़े खरीदारों में से है।

पीजीसीए अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आता है। पीजीसए ने कहा है कि परमिट दुश्मन देशों (इजरायल, अमेरिका और इनके सहयोगी देश) को नहीं दिए जाएंगे। ईरान ने पीजीसीए को श्दुश्मन देशोंश के जहाजों को अनुमति देने का अधिकार नहीं दिया है। ईरान के दोस्त देशों और सहयोगी सरकारों से जुड़े जहाजों को गुजरने में प्राथमिकता दी जा रही है।

पीजीसीए ने नहीं बताया है कि होर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों से कितना शुल्क लिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट कहती है कि एक तेल टैंकर से ईरान 2 मिलियन डॉलर ले सकता है। दूसरी ओर अमेरिका ने जहाजों को निर्देश दिया है कि वे ईरान को किसी भी फीस का भुगतान नहीं किया जाए। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने पीजीसीए पर प्रतिबंध लगाए है।

अमेरिका और ईरान के बीच बीते तीन महीने से ज्यादा समय से तनाव चरम पर है। अमे. रिका–इजरायल गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले शुरू किए थे। अमे. रिका–इजरायल के हमलों के बाद पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में आ गया था।

ईरान ने हमलों के जवाब में जो कदम उठाए, उनमें होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना शामिल था। ईरानी सेना की ओर से होर्मुज का यातायात रोकने के बाद से यह समुद्री गलियारा चर्चा में है।

इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ने ईरानी बंद. रगाहों पर नाकेबंदी लगा रखी है। अमेरिका और ईरान मध्यस्थों के जरिए होर्मुज पर आम सहमति बनाने में सफल नहीं हुए है। ईरान की कोशिश होर्मुज में स्थायी टोल बूथ बनाने की है। अमेरिका इसका विरोध कर रहा है।

Created by Universal Document Converter

सम्पादकीय

पद का हस्तांतरण?

कर्नाटक में सत्ता का सुचारू हस्तांतरण समकालीन भारतीय राजनीति में अनुशासन के एक दुर्लभ प्रदर्शन के रूप में सराहा गया है। एक मुख्यमंत्री ने बिना किसी सार्वजनिक विद्रोह के इस्तीफा दे दिया, उनके लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी को सर्वसम्मति से उनका उत्तराधिकारी चुना गया, और सत्ताधारी पार्टी ने इस बदलाव के हर चरण पर एकता का प्रदर्शन किया। फिर भी, इस पूरी व्यवस्था के पीछे एक अधिक जटिल प्रश्न छिपा हैरू क्या कर्नाटक ने वास्तव में सत्ता का हस्तांतरण देखा है, या केवल पद का हस्तांतरण?

डी.के. शिवकुमार का मुख्यमंत्री पद पर आसीन होना एक ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की परिणति है जिसने वर्षों से कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति को आकार दिया है। पार्टी के सबसे प्रभावशाली संगठक और इसके सबसे कद्दावर राजनीतिक रणनीतिकारों में से एक के रूप में, श्री शिवकुमार यथोचित रूप से यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने यह पद अपनी मेहनत से अर्जित किया है। साथ ही, जिस तरह से श्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ा, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एक ऐसे नेता के लिए जो अपने पूरे करियर में अपनी सत्ता को कम करने के प्रयासों का विरोध करने के लिए जाने जाते रहे हैं, पार्टी नेतृत्व के फैसले को श्री सिद्धारमैया द्वारा स्वीकार करना काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने न तो अपने समर्थकों को लामबंद किया और न ही इस बदलाव को चुनौती दी।

इसके बजाय, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने उत्तराधिकारी का समर्थन किया और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा पर जोर दिया। इस तरह के आचरण ने उनके कद को कम करने के बजाय और बढ़ाया ही है। राजनीति में, स्वेच्छिक संयम अक्सर एक अलग तरह की शक्ति पैदा करता है। यही कारण है कि बुधवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तुलना में आने वाले महीने अधिक मायने रखेंगे। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि मुख्यमंत्री के पद पर कौन आसीन है। बल्कि प्रश्न यह है कि क्या कर्नाटक की सत्ताधारी पार्टी सत्ता के किसी एक ही केंद्र से सुचारू रूप से कार्य कर पाएगी।

श्री सिद्धारमैया राज्य में कांग्रेस पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण जन नेता बने हुए हैं। उनका प्रभाव विधायकों, सामाजिक गठबंधनों और क्षेत्रीय नेटवर्कों तक फैला हुआ है, जिन्होंने 2023 में पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय राजनीति में जाने के अवसरों को ठुकराकर और राज्य के मामलों में अपनी निरंतर सक्रियता का संकेत देकर, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल संन्यास लेने का उनका कोई विचार नहीं है।

उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है। यह स्थिति एक अवसर और एक चुनौती, दोनों ही पैदा करती है। एक ओर, कांग्रेस उन दो नेताओं की संयुक्त ताकत से लाभान्वित हो सकती है, जिनकी अपील अलग–अलग वर्गों के मतदाताओं के बीच है और जो शासन तथा चुनावी राजनीति में अपने–अपने विशिष्ट कौशल का योगदान देते हैं। दूसरी ओर, भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जब सत्ता के विभिन्न प्रतिस्पर्धी केंद्रों के आपसी टकराव के कारण सरकारें कमजोर पड़ गई हैं। यदि सत्ता का विभाजन होने का आभास होता है, तो मंत्रिमंडल का गठन, विभागों का बंटवारा, संगठनात्मक नियुक्तियाँ और उम्मीदवारों का चयन जैसे मुद्दे बहुत जल्द ही आपसी खींचतान और विवाद का अखाड़ा बन सकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व के लिए, तात्कालिक लक्ष्य हासिल हो गया है। उत्तराधिकार की एक संभावित रूप से उथल–पुथल मचाने वाली लड़ाई को बिना किसी स्पष्ट हंगामे के संभाल लिया गया है। यह अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, खासकर ऐसी पार्टी में जिसे अक्सर राज्य–स्तरीय नेतृत्व परिवर्तन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। फिर भी, राजनीतिक स्थिरता का पैमाना यह नहीं होता कि कोई परिवर्तन कैसे शुरू होता है, बल्कि यह होता है कि उसके बाद शासन–प्रशासन कैसे चलता है।

कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को जल्द ही यह एहसास हो जाएगा कि पद पर बैठना, उस पद के भीतर अपनी सत्ता को मजबूत करने से कहीं ज्यादा आसान है। हो सकता है कि राज्य ने उत्तराधिकार के संकट को टाल दिया हो। लेकिन क्या उसने भविष्य में होने वाली सत्ता की लड़ाई को भी टाल दिया है, यह अभी भी एक खुला सवाल है। इसका जवाब न केवल नई सरकार के टिकने की अवधि तय करेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण गढ़ों में से एक में उसके भविष्य की संभावनाओं को भी निर्धारित करेगा।

आकाश पर राज करेगी भारतीय वायुसेना, दक्षिण एशिया में ताकत के सारे समीकरण बदलकर रख देंगे 114 Rafale Jets

नीरज कुमार दुबे

भारत ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान को साफ चेतावनी दे दी है कि अब नया भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि दुश्मन की रणनीति को जड़ से तोड़ने की ताकत रखता है। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल युद्धक विमानों की खरीद का फैसला दक्षिण एशिया में ताकत का पूरा समीकरण बदलने वाली चाल है। करीब तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये के इस महा समझौते ने बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों की नींद उड़ा दी है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से ठीक पहले उठाया गया यह कदम दुनिया को साफ संदेश देता है कि भारत अपनी सैन्य ताकत को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ने देगा।

देखा जाये तो भारतीय वायुसेना इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर में खड़ी है। स्वीकृत 42.5 पांच स्क्वॉड्रन के मुकाबले उसके पास केवल 29 स्क्वॉड्रन बचे हैं। दूसरी ओर चीन तेजी से अपने पांचवीं और छठी पीढ़ी के युद्धक विमानों का जाल खड़ा कर रहा है। चीन के पास पहले से जे–20 और जे–35 जैसे स्टेल्थ विमान सक्रिय हैं, जबकि वह जे–36 और जे–50 जैसे अगली पीढ़ी के विमानों का परीक्षण भी कर रहा है। पाकिस्तान भी चीन के सहयोग से जे–35 ए जैसे स्टेल्थ विमान हासिल करने की तैयारी में है। ऐसे माहौल में भारत का राफेल पर दांव केवल जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्णायक प्रश्न बन चुका है।

भारतीय वायुसेना ने पिछले वर्षों में जिस अदम्य साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया है, उसने दुनिया को भारत की नई सैन्य सोच का परिचय दिया है। बालाकोट से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा तक भारतीय

वायुसेना ने यह साबित किया कि वह दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देने की क्षमता रखती है। अब वही वायुसेना राफेल जैसे घातक और आधुनिक युद्धक विमानों से और अधिक प्रचंड होने जा रही है। देखा जाये तो राफेल केवल विमान नहीं, बल्कि हवा में भारत की दहाड़ है। इसकी मारक क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की ताकत और दुश्मन की वायु रक्षा को ध्वस्त करने की क्षमता इसे बेहद घातक बनाती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते के तहत अठारह विमान सीधे फ्रांस से आएंगे, जबकि 96 विमानों का निर्माण भारत में होगा। यह पहली बार होगा जब राफेल का निर्माण फ्रांस के बाहर किया जाएगा। लगभग पचास प्रतिशत स्वदेशीकरण के साथ यह कार्यक्रम भारत को केवल खरीदार नहीं, बल्कि रक्षा निर्माण शक्ति बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे भारत की रक्षा औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी, हजारों रोजगार पैदा होंगे और भविष्य में स्वदेशी युद्धक विमान कार्यक्रमों को भी नई गति मिलेगी।

हालांकि यह भी सच है कि केवल राफेल से पूरी समस्या का समाधान नहीं होगा। मिग–29, मिराज–2000 और जगुआर जैसे पुराने विमान अगले दशक में सेवा से बाहर होने लगेंगे। दूसरी ओर तेजस मार्क–1 ए और तेजस मार्क–2 जैसी स्वदेशी परियोजनाएं देरी से जूझ रही हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना को संख्या और तकनीक दोनों स्तरों पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस संकट के बीच भी भारत ने बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है। एक ओर राफेल, दूसरी ओर उन्नत मध्यम युद्धक विमान कार्यक्रम और साथ ही मानव रहित युद्धक प्रणालियों पर निवेश, यह दिखाता है कि नई दिल्ली आने वाले बीस वर्षों की हवाई शक्ति संरचना तैयार कर रही है।

हम आपको यह भी बता दें कि दुनिया की दो बड़ी छठी पीढ़ी की परियोजनाएं भी इस समय संकट में हैं। ब्रिटेन, इटली और जापान का वैश्विक युद्धक विमान कार्यक्रम वित्तीय संकट और देरी का शिकार है, जबकि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की भविष्य वायु युद्ध प्रणाली आंतरिक टकराव में फंसी हुई है। भारत ने इन दोनों परियोजनाओं में रुचि दिखाई थी, लेकिन अब वहां अनिश्चितता बढ़ गई है। यही कारण है कि भारत ने तत्काल सामरिक मजबूती के लिए राफेल पर भरोसा बढ़ाया है।

इसके अलावा, रूस का सुखोई–57 भी चर्चा में है। रूस भारत को तकनीक हस्तांतरण, स्रोत कोड और भारत में निर्माण जैसे आकर्षक प्रस्ताव दे रहा है। कई पूर्व वायुसेना अधिकारियों का मानना है कि सीमित संख्या में सुखोई–57 विमानों की खरीद भारत के लिए अंतरिम समाधान हो सकती है। लेकिन भारत फिलहाल किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर होने की बजाय बहुध्रुवीय रक्षा रणनीति अपना रहा है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है।

प्रधानमंत्री मोदी की आगामी फ्रांस यात्रा इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। यह यात्रा भारत और फ्रांस के बीच उभरती सामरिक साझेदारी का निर्णायक चरण साबित हो सकती है। अमेरिका के साथ हाल के तनाव और पश्चिमी देशों की अनिश्चित नीतियों के बीच फ्रांस ऐसा साझेदार बनकर उभरा है जो भारत को तकनीक, उत्पादन और रणनीतिक सहयोग तीनों देने को तैयार दिख रहा है। चीन को घेरने की वैश्विक रणनीति में भारत और फ्रांस का यह गठजोड़ हिंद महासागर से लेकर प्रशांत क्षेत्र तक नई शक्ति संतुलन रचना कर सकता है।

दक्षिण एशिया में इसका सबसे गहरा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट और सैन्य निर्भरता से जूझ रहा है। ऐसे समय में भारत का 200 से अधिक राफेल विमानों की दिशा में बढ़ना पाकिस्तान की वायु शक्ति को पूरी तरह असंतुलित कर देगा। चीन भले ही पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दे, लेकिन भारतीय वायुसेना का युद्ध अनुभव, प्रशिक्षण स्तर और तकनीकी समन्वय पाकिस्तान के लिए भय का कारण बना रहेगा। राफेल की मौजूदगी से भारत को दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में भी निर्णायक बढ़त मिलने की संभावना मजबूत होगी।

बहरहाल, स्पष्ट है कि यह समझौता भारत की नई सैन्य सोच का उद्घोष है। संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत अब इंतजार नहीं करेगा, भारत अब जवाब देगा। भारतीय वायुसेना की गर्जना आने वाले वर्षों में और प्रचंड होने वाली है। राफेल के पंखों पर सवार होकर भारत केवल अपनी सीमाएं सुरक्षित नहीं करेगा, बल्कि पूरे एशिया में शक्ति संतुलन की नई कहानी लिखेगा।

ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कासल पर इजरायली झंडा देख ईरान ने ऐसा धमकाया, ट्रंप–नेतन्याहू के बीच गाली–गलौच तक हो गई?

अभिनय आकाश

2 मई का दिन जब हाथों में ऊनों के सारे वाइल्ड कार्ड को थामे ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर तस्वीर पोस्ट की थी। इस पर लिखा था आई हैव ऑल द कार्डस। तब इसे ईरान जंग से जोड़कर देखा गया था। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए नया–नया एक प्लान बनाया था और उसी की खुशी सोशल मीडिया पर वो बांट रहे थे। अब वो प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में जा चुका है और शायद ट्रंप का यह दावा भी। तभी तो ईरान की एक धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप अपने पक्के पक्के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं बख्श रहे हैं। खबर है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन मिलाया, जमकर लताड़ लगाई, बात गाली गलौज तक पहुंच गई। लेकिन क्यों? ईरान से ऐसी क्या धमकी थी जिसकी वजह से ट्रंप ने यह कदम उठाया? क्या नेतन्याहू की वजह से ईरान डील अटक जाएगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों का एमआरआई स्कैन करेंगे।

अपने पक्के दोस्त नेतन्याहू पर क्यों भड़क गए ट्रंप?

तुम पागल हो। अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। अब सब तुमसे और इजराइल से नफरत करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने यह बातें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को एक फोन कॉल के दौरान कही। इस फोन कॉल की जानकारी एक्सिस को दो अमेरिकी अधिकारियों ने दी। नेतन्याहू की ओर से लेबनान पर करवाए जा रहे हमले से ट्रंप भड़क गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया तो दुनिया में इजराइल और अलग–थलग पड़ जाएगा। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि मैंने नेतन्याहू को जेल जाने से बचाने में मदद की। दरअसल, साल 2020 में इजराइली पीएम नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल शुरू हुआ था। नेतन्याहू पर यह आरोप थे कि उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कुछ बड़े बिजनेसमैन से महंगे गिफ्ट्स लिए हैं। बॉलीवुड प्रोड्यूसर से भी गिफ्ट्स लिए हैं और बदले में उन्हें फायदा पहुंचाया। साथ ही साथ कुछ मीडिया कंपनीज के साथ भी सेटिंग करके अपने पक्ष में खबरें दिखवाने की कोशिश की। नेतन्याहू इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन पर पद पर रहते हुए क्रिमिनल केस चला। तब ट्रंप ने इजरायल के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था।

दोनों नेताओं के सोशल पोस्ट कुछ और ही कहानी कहते नजर आए

1 जून को हुई इस फोन कॉल से एक दिन पहले ही ईरान ने यह वार्निंग दे दी थी कि अगर इजराइल लेबनान में अपने ऑपरेशंस जारी रखता है तो वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है और इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल बेरूत पर हमले ना करें। कॉल के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है। अपने ट्रूप सोशल पर भी उन्होंने यह पोस्ट किया और रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि इस बातचीत में ट्रंप ने पूरी तरह दबाव बना लिया। आखिर में नेतन्याहू को बात माननी ही पड़ी और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता तैयार हो रहा है उसमें लेबनान में लड़ाई खत्म करने की बात भी शामिल है। हालांकि ट्रंप को यह भी पता था कि हिजबुल्ला इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और इजराइल को अपनी रक्षा का भी हक है। लेकिन ट्रंप को लगा कि नेतन्याहू जरूरत से ज्यादा अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को एस्केलेट कर रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर डोनल्ड ट्रंप ने लिखा कि मेरी इजराइली प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू से बहुत बढ़िया बात हुई। अब बेरूत की सड़कों पर इजराइली सैनिक नजर नहीं आएंगे। जो पहले ही जा चुके हैं वह अब लौट रहे हैं। इसी तरह मेरे प्रतिनिधियों ने हिजबुल्ला से भी बातचीत की। वह हमलों को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पोस्ट किया और लिखा कि मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई। भी मैंने उन्हें कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरों हमारे लोगों पर हमले नहीं रोकेगा तो हम दोबारा बेरूत को निशाना बनाएंगे। हमारी सेना आईडीएफ दक्षिणी लेबनान ने अपना ऑपरेशन प्लान के मुताबिक जारी रखेगी। यानी नेतन्याहू बेरूत में हमला रोकने के लिए तो मान गए लेकिन साउथ लेबनान में इजराइल हमले करता रहेगा। इस पूरे वाक्य से यह तो साफ हो गया है कि ट्रंप के लिए ईरान के साथ डील करना कितना ज्यादा जरूरी है। वो नहीं चाहते कि किसी भी थर्ड फैक्टर की वजह से यह डील अटक जाए। ट्रंप की इच्छा वाजिब भी है। अमेरिका के हालात इस वक्त ट्रंप की राजनीति के लिए सही नहीं है। गैस की कीमतें जंग से पहले 2 से +.5 प्रति गैलन होती हैं जो अब +4.5 को भी पार कर चुकी हैं। मिड टर्म इलेक्शन भी सर पर है और जंग की वजह से ट्रंप अपनी पार्टी के अंदर भी अनपॉपुलर लगातार होते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहते जिससे ईरान डील से पीछे हट जाए।

क्या ईरान की धमकी से डरे ट्रम्प, क्यों हुए इतने नाराज

ट्रम्प प्रशासन ईरान से शांति समझौते के लिए वार्ता कर रहा है। नेतन्याहू द्वारा बेरूत पर हमले जारी रखने से ट्रम्प की पूरी कूटनीति दांव पर लग गई, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति भड़क गए। नेतन्याहू की सैन्य कार्रवाइयों और नागरिकों की मौतों के कारण दुनिया भर में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अमेरिकी जनता मिडिल ईस्ट के युद्धों से थक चुकी है। ट्रम्प भी अब अपनी बड़ी प्राथमिकताओं (जैसे चीन नीति और घरेलू अर्थव्यवस्था) पर ध्यान देना चाहते हैं। इस जंग से निकलना चाहते हैं। अगर नेतन्याहू के कारण ईरान और लेबनान में युद्ध और भड़कता है, तो वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ेगी और अमेरिका एक अंतहीन जंग में फंस जाएगा, जो ट्रम्प को अपनी घरेलू राजनीति के लिए मंजूर नहीं है।

ऐसे बढ़ रहा पुराने दोस्तों के बीच तनाव

गाजा युद्ध, ईरान रणनीति और युद्धविराम को लेकर ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच दरार बढ़ती गई। 2020 में नेतन्याहू ने अमेरिकी चुनाव के तुरंत बाद जो बाइडेन को बधाई दी थी। इससे नाराज ट्रम्प ने नेतन्याहू के लिए अपशब्द तक कहा था। ट्रम्प ने आरोप लगाया था कि कासिम सुलेमानी पर अमेरिकी हमले के समय नेतन्याहू आखिरी वक्त में पीछे हट गए थे। कहा मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। 2023 में हमास हमले के बाद ट्रम्प ने सहानुभूति जताने के बजाय ट्रम्प ने सार्वजनिक रैली में नेतन्याहू की खुफिया विफलता की कड़ी आलोचना की और हिजबुल्लाह को श्स्मार्टश कह दिया। 2024 में ट्रम्प लगातार दबाव बनाते रहे कि इजरायल गाजा में जंग जल्द खत्म करे, पर नेतन्याहू अपनी घरेलू राजनीति के लिए युद्ध को लंबा खींचते रहे।

विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा महंगाईरू ईरान में मई 2026 में महंगाई दर 77.2: पर पहुंच गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। दवाइयों, टैक्सी किराये और संचार जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की कीमते एक साल में 113.8: बढ़ गई। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत भी बुरी तरह गिरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के कारण फिर बड़े विरोध–प्रदर्शन भड़क सकते हैं।

विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा महंगाई

ईरान में मई 2026 में महंगाई दर 77.2: पर पहुंच गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। दवाइयों, टैक्सी किराये और संचार जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की कीमते एक साल में 113.8: बढ़ गई। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत भी बुरी तरह गिरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के कारण फिर बड़े विरोध–प्रदर्शन भड़क सकते हैं।

ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कासल पर इजरायल का कब्जा

इजराइल और लेबनान के बीच में पहला सीज फायर 17 अप्रैल को हुआ था। 15 मई को इसे 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन सीजफायर के बावजूद इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। उसका तर्क है कि यह हमले हिजबुल्लाह के खिलाफ सेल्फ डिफेंस है। इसलिए यह सीजफायर का उल्लंघन नहीं है। लेबनान की पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 25 मई से 1 जून तक इजराइल के हमलों में करीब 250 लोग मारे गए। तो फिर ईरान ने अब बातचीत बंद करने की धमकी क्यों दी? वजह है इजराइल का 31 मई को लेबनान में इजराइली सेना का ऑपरेशन। इसमें इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कासल पर कब्जा कर लिया है। कासल यानी किला समझिए। इजराइली सेना ने एक वीडियो इस बारे में जारी किया जिसमें इस किले पर इजराइयली झंडा लहराता नजर आया। यह किला रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। यह दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी की घाटी के ठीक ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर बना है और इजराइल की सरहद से 14.5 कि.मी. दूर है। यहां से पूरे इलाके पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। इस किले का इतिहास करीब 900 साल पुराना है। इसे क्रुसेडर्स यानी धर्म युद्ध लड़ने वाले ईसाइयों ने बनवाया था। 44 साल पहले 1982 में इजराइल ने इसी किले पर पहली बार कब्जा जमाया था। तब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के लड़ाके इस किले पर काबिज थे। इजराइल ने पूरे 18 साल यानी 1982 से लेकर 2000 तक इस किले में अपनी मिलिट्री पोस्ट बनाए रखी। अब 18 बरसों में हिजबुल्ला और दूसरे चरमपंथी इस किले पर लगातार गोरिल्ला हमले करते रहे। इजराइयली सैनिकों के लिए वहां ड्यूटी करना कभी भी आसान नहीं था। इस किले के नाम पर ब्यूफोर्ट नाम की एक मशहूर फिल्म भी बनी थी जिसे ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। साल 2000 में जब इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाई तो यह किला भी खाली कर दिया। 26 साल बाद इजराइली झंडा एक बार फिर इस किले पर लहराया गया। इस बात ने हिजबुल्ला और ईरान दोनों को बेचैन कर दिया।

Created by Universal Document Converter

कठुआ विधायक ने विकास कार्यों के लिए जारी किए 1 करोड़, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में तेज होगी रफ्तार

संवाददाता

कठुआ। कठुआ के विधायक डॉ. भारत भूषण ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से एक करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह राशि क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में खर्च की जाएगी।

विधायक ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष लगभग 4.75 करोड़ रुपये की राशि से स्वीकृत अधिकांश कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जबकि करीब 20 कार्य अभी प्रगति पर हैं। इन कार्यों में बोरवेल स्थापना, गलियों और नालियों का निर्माण, डीप कवर नालों का निर्माण, सुरक्षा कार्य, बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत, पुलियों का निर्माण, सड़कों का ब्लैकटॉपिंग, बिजली सुविधाओं का स्थानांतरण तथा बेघर परिवारों को सहायता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई एक करोड़ रुपये की राशि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसके अलावा आवास, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग के तहत भी बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कठुआ विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

सफाईकर्मियों की हड़ताल के बीच विधायक मोहन लाल ने संभाली कमान, स्वयं झाड़ू उठाकर चलाया स्वच्छता अभियान

संवाददाता

अखनूर (मोहन सिंह)। सफाईकर्मियों की जारी हड़ताल के कारण कस्बे में बिगड़ती सफाई व्यवस्था और बढ़ती गंदगी को देखते हुए बुधवार सुबह विधायक अखनूर मोहन लाल भगत ने स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर मुख्य बाजार में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया।

सुबह आयोजित यह अभियान विधायक कार्यालय से शुरू हुआ और मुख्य बस स्टैंड, मुख्य बाजार, शर्मा स्वीट्स होते हुए निर्दोष चौक तक चलाया गया। अभियान के दौरान सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर जमा कूड़े–कचरे को हटाया गया तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।

इस अवसर पर विधायक मोहन लाल ने कहा कि सफाईकर्मियों की जायज मांगों का वह समर्थन करते है और सरकार से उनके मुद्दों के समाधान की अपेक्षा रखते

हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल के चलते शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और समाज के सभी वर्गों का दायित्व बनता है कि वे शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।

उन्होंने नागरिकों और व्यापारी वर्ग से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों और दुकानों का कूड़ा निर्धारित कूड़ेदानों में ही डालें तथा नालों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से बचें। उन्होंने कहा कि घर साफ होंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी और बाजार साफ होंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा।

अभियान में सिविल सोसायटी अखनूर, संत निरंकारी मिशन, हरि मंदिर शिव घाट, भारत विकास परिषद, भाजपा युवा मोर्चा, भाजपा मंडल अखनूर, मानस परिवार, मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अभियान के दौरान लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने और नगर को साफ–सुथरा रखने का संकल्प भी लिया।

अखनूर में "आस डोगरे, जम्मू शहर दे" गीत का भव्य लॉन्च

संवाददाता

अखनूर। अखनूर में हाई फीट स्टूडियोज़, रामा पैलेस में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जुगल चनन द्वारा लिखा गया और शिव देबंडा द्वारा गाया गया नया डोगरी गीत "आस डोगरे जम्मू शहर दे" लॉन्च किया गया। इस गीत का पोस्टर भी इस मौके पर जारी किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखनूर के विधायक मो. हनलाल भगत जी और विशेष अतिथि श्रीमती रानो शर्मा रहे। जुगल चनन ने इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा पल है। उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने 200 से अधिक गीत लिखे हैं और उनका प्रयास है कि हर माह कम से कम एक गीत के माध्यम से डोगरी भाषा को बढ़ावा दें।

विधायक मोहनलाल भगत ने कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास हमारी मातृभाषा डोगरी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने

बच्चों को डोगरी सिखाएं, लिखना, बोलना और कार्यों में प्रयोग करना हमारी सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर की सेवा है। उन्होंने यह भी बताया कि डोगरी भाषा अब आठवें शेड्यूल में शामिल हो चुकी है और राज्य जम्मू–कश्मीर में सरकारी भाषा का दर्जा भी प्राप्त कर चुकी है।

इस अवसर पर शिव देबंडा, रानो देवी, राकेश मल्होत्रा, विक्रांत शर्मा, सुशील शर्मा, अजय शर्मा, अंजू देवी, गणेश दत्त, अश्वनी, राजू मास्टर, कुलदीप टीकू, रमन कुमार, रतन भारद्वाज, केवल कुमार, मोहन पंडित मिश्रा समेत बड़ी संख्या में डोगरे प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। यह आयोजन डोगरी भाषा और संस्कृति के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इस प्रकार के प्रयासों से हमारी मातृभाषा को नई पहचान और प्रेरणा मिलती है।

दैहमा रैपर में खून व मजालता के लोगों द्वारा आयोजित किया गया महत्वपूर्ण कार्यक्रम

रैली निकाल कर जताया रोष, दिया धरना, संबंधित अधिकारी ने मौके पर पहुंच सुनी लोगों की समस्याएं

संवाददाता

उधमपुर (संजीव शर्मा)। उधमपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के दैहमा रैपर, तहसील मजालता के खून एवं मजालता ब्लॉक के प्रमुख कार्यकर्ताओं, स्थानीय निवासियों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र से जुड़े जनहित के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके उपरांत एक रोष रैली भी निकाली गई तथा मुख्य मार्ग पर सड़क मार्ग बंद कर धरना भी दिया गया। वहीं धरने की जानकारी मिलते ही प्रशास. निक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पवन खजूरिया द्वारा समस्याओं का एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा जिसके जरिए सरकार और प्रशासन से इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई।

कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता पवन खजूरिया, पूर्व सरपंच पोली देवी, पूर्व सरपंच रीता देवी, कैप्टन गोपाल सिंह, बिशन दास, बलवंत राज, बाबू राम, मास्टर दुर्गा दास, केवल शर्मा, फिरोजदीन, अशोक गुप्ता, संदीप गुप्ता, पूर्व सरपंच हंस राज, मक्खन लाल, पूर्व सरपंच राजेश शर्मा, मोहम्मद शफी, करतार सिंह, गोविंद राम, पूरी सिंह, पूर्व सरपंच बोध राज रैना, पूर्व सरपंच मुकंद, राज कुमार बुच्चा, पूर्व सरपंच राम सिंह, पूर्व सरपंच गौतम, कैप्टन योग राज, मुजम्मिल, सुरेश कुमार, जालिम सिंह, गुरुदयाल, कुलदीप, विजय कुमार, संजय, राकेश शर्मा सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे और क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को मजबूती से उठाया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि उधमपुर सहित पूरे जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन योजना का कार्य अभी तक अपेक्षित गति से पूरा नहीं हो पाया है। सरकार ने 'हर घर जल' का जो सपना लोगों को दिखाया था, वह आज भी अनेक गांवों में अधूरा है। कई क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य

अधूरा पड़ा है, जबकि कहीं जलापूर्ति नियमित नहीं है। वक्ताओं ने मांग की कि जल जीवन मिशन के कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध हो सके और योजना का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचे।

कार्यक्रम में ग्रामीण संपर्क सड़कों की जर्जर स्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। इसके अलावा वक्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राम सभा में जो कार्य जनता द्वारा पंचायत स्तर पर रखे गए थे उन्हें बाद में ब्लॉक के अधिका. रियों द्वारा किसी के दबाव में आकर बदला गया, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस अवसर पर पवन खजूरिया ने कहा कि पिछले वर्ष की बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुए अधिकांश लिंक रोड, जो गांवों को धार रोड तथा अन्य मुख्य सड़कों से जोड़ते हैं, आज भी बदहाल स्थिति में पड़े हुए हैं। कई स्थानों पर सड़कें टूट चुकी हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब जबकि इस महीने से पुनः वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है, प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इन सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करना चाहिए, ताकि बरसात के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क प्रभावित न हो।

इस अवसर पर वक्ताओं ने यह भी कहा कि क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सक्रियता केवल सीडीएफ तक सीमित होकर रह गई है। विकास कार्यों के लिए उपलब्ध अन्य योजनाओं और फंडों को लेकर कोई गंभीर प्रयास दिखाई नहीं देता। वक्ताओं ने कहा कि जनप्रति. निधियों का दायित्व केवल सीमित निधियों तक नहीं बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों और योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक संसाधन लाना भी है। दुर्भाग्यवश इस दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा की और संबंधित विभागों से इनका शीघ्र समाधान करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि यदि जनसमस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो आम जनता को साथ लेकर व्यापक जनआंदोलन चलाने पर भी विचार किया जाएगा।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने क्षेत्र के विकास, जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने तथा जनता की आवाज बनने के लिये और अपनी आवाज को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए वरिष्ठ नेता पवन खजूरिया का धन्यवाद किया और किसी भी स्थिति में सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।

मेरे युवा भारत विभाग ने वर्ल्ड साइकिलिंग डे पर आयोजित की साइकिल रैली

विधायक पवन गुप्ता ने दिखाई झंडी ईंधन को बचाने का दिया संदेश

संवाददाता

उधमपुर (संजीव शर्मा)। मेरे युवा भारत विभाग द्वारा बुधवार को वर्ल्ड साइकिलिंग डे पर उधमपुर सुभाष स्टेडियम से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश था, लोगों फिट रहने के लिए साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना।

इस दौरान उनके द्वारा साइकिलिंग के जरिए प्रधान मंत्री द्वारा ईंधन बचाने के लिए जो संदेश दिया गया था उसके लिए भी लोगों को साइकिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने व ईंधन को बचाने का भी संदेश दिया। इस अवसर पर उधमपुर वेस्ट के विधायक पवन कुमार गुप्ता द्वारा सुभाष स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि शहर के मुख्य चौक–चौराहों से होते हुए मिनी स्टेडियम में जाकर संपन्न हुई।

अखबार-ज्ञान, सत्य और जागरूकता का सबसे भरोसेमंद साथी

संवाददाता

–पूनम झा–

आज के डिजिटल युग में जहाँ सूचना के अनेक माध्यम उपलब्ध हैं, वहीं अखबार आज भी सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। दैनिक समाचारों से लेकर किसी विषय की गहन और विस्तृत जानकारी तक, अखबार हमें संतुलित, जांची–परखी और तथ्यपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। टेलीविजन समाचार या आम चर्चाएँ अक्सर समय की सीमा में बंधी होती हैं, जिसके कारण विषय की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, जबकि अखबार हर पहलू को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं।

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच सही और गलत जानकारी में अंतर करना कठिन हो गया है। बिना सत्यापन के फैलने वाली खबरें कई बार भ्रम पैदा करती हैं। ऐसे में अखबारों की विश्वसनीयता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर आंख मूंदकर विश्वास करने के बजाय अखबारों जैसे प्रमाणिक स्रोतों को प्राथमिकता दें, ताकि हमें सही और तथ्यपूर्ण जानकारी मिल सके। अखबार केवल समाचारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह ज्ञान का एक व्यापक भंडार हैं। देश–विदेश की घटनाओं, राजनीति, व्यापार, खेल, विज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक विषयों की जानक. ारी के साथ–साथ इसमें वर्ग पहेलियाँ, स्वास्थ्य संबंधी लेख, फैशन, खान–पान और रोचक किस्से भी शामिल होते हैं। इससे न केवल हमारा सामान्य

ज्ञान बढ़ता है, बल्कि भाषा और शब्द–भंडार में भी सुधार होता है। कई लोग सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जो एक अच्छी आदत है। यह आदत व्यक्ति को जागरूक, समझदार और समाज से जुड़ा हुआ बनाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर आईएएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी में भी अखबार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनमें समसामयिक घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। अखबार पढ़ने के बाद भी उनके अनेक उपयोग हैं। पुराने अखबारों से सामान लपेटने, सफाई करने, अलमारियों में बिछाने के अलावा सुंदर हस्तशिल्प और सजावटी वस्तुएँ भी बनाई जाती हैं। इस प्रकार अखबार उपयोगी होने के साथ–साथ रचनात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं। यदि बच्चों में बचपन से ही अखबार पढ़ने की आदत डाली जाए, तो उनमें पढ़ने की रुचि विकसित होती है और उनका मानसिक विकास बेहतर होता है। यह आदत उनके व्यक्तित्व निर्माण और उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। गाँव–गाँव तक समाचार पहुँचाने में अखबारों की ऐतिहा. सिक भूमिका रही है। आज भी, तकनीक के इस युग में, अखबार अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के कारण लोगा. के बीच सम्मानित हैं। इनके प्रकाशन में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का परिश्रम सराहनीय है, जो हर सुबह हमें ताजा खबरें उपलब्ध कराते हैं। अंततः, यह कहना उचित होगा कि "ओल्ड इज गोल्ड" पुरानी चीजों का महत्व कभी कम नहीं होता। अखबार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हमें नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और इस महत्वपूर्ण माध्यम को प्रोत्साहित करना चाहिए।

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते अखनूर में लगे गंदगी के ढेर। इसकी साफ सफाई के लिए आज धार्मिक स्थलों पर हरि मंदिर घाट सेवा संस्था द्वारा खुद सफाई करके शहर को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया।

छायाः मोहन सिंह जम्वाल।

कठुआ में शहीद सतपाल सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

संवाददाता

कठुआ। जिले के वीर सपूत शहीद नायब सूबेदार सतपाल सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर बुधवार को कठुआ में भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिवारजनों, पूर्व सैनिकों, जनप्रति. निधियों तथा विभिन्न वर्गों के लोगों ने एकत्रित होकर शहीद को नमन किया। ज्ञात हो कि नायब सूबेदार सतपाल सिंह, जो जम्मू–कश्मीर राइफल्स की 23वीं बटालियन में तैनात थे, ने 3 जून 2025 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत–चीन सीमा पर देश की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। कार्यक्रम में विधायक कठुआ डॉ. भारत भूषण, शहीद के परिजन, पूर्व सेना अधिकारी एवं जवान, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति को याद किया। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और देशभक्ति के नारे लगाकर शहीद के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया।

विधायक डॉ. भारत भूषण ने अपने संबोधन में कहा कि देश के वीर शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के जीवन से प्रेरणा लें और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। उन्होंने कहा कि शहीद दिवस का आयोजन न केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, बल्कि यह देशभक्ति की भावना को और सुदृढ़ करने का भी माध्यम है। इस मौके पर कैप्टन पवन कुमार शर्मा, कैप्टन महात्मा सिंह, कैप्टन सूरज सिंह, कैप्टन प्रेम सिंह, कैप्टन नसीब सिंह, कैप्टन जगदीश सिंह, समाजसेवी अशोक शर्मा, सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह का समापन शहीद के प्रति दो मिनट का मौन रखकर किया गया।

सत्या पॉल ने लंदन में प्रिंट, ड्रेप और कलात्मक अभिव्यक्ति की अपनी विरासत को किया प्रदर्शित

संवाददाता

लंदन, 3 जून 2026। भारत के प्रतिष्ठित फैशन ब्रांड सत्या पॉल (Satya Paul) ने एसएक्सएसडब्ल्यू लंदन (SXSW London) में अपने विशेष शोकेस अनटेम्ड (Untamed) के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को नए अंदाज में प्रस्तुत किया। यह आयोजन लंदन के ऐतिहासिक लैंकेस्टर हाउस (Lancaster House) में हुआ।

क्रिएटिव डायरेक्टर असीम कपूर के नेतृत्व में यह सत्या पॉल की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति थी। इसके साथ ही ब्रांड ने अपने मेन्स वियर (Menswear) कलेक्शन को भी पहली बार वैश्विक दर्शकों के सामने पेश किया।

यह शो यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड के आमंत्रण पर

आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फैशन, कला, संगीत और मूवमेंट का अनूठा संगम देखने को मिला। अनटेम्ड सत्या पॉल की स्वतंत्र सोच, आत्म–अभिव्यक्ति और रचनात्मक स्वतंत्रता का प्रतीक बना। शो में प्रिंट, ड्रेप, मूवमेंट और संगीत को एक साथ जोड़कर एक खास सांस्कृतिक अनुभव तैयार किया गया।

प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण साड़ी रही, जिसे सत्या पॉल की पहचान माना जाता है। साड़ियों को नए और आधुनिक ड्रेप्स के साथ प्रस्तुत किया गया। डिजाइनों में प्रकृति, इतिहास और भारतीय मूर्तिकला की झलक दिखाई दी।

रंगों से भरपूर प्रिंट्स, नई सिल्हूट्स और प्रयोगधर्मी ड्रेपिंग ने कलेक्शन को अलग पहचान दी। शो में ब्रांड के प्रसिद्ध जेब्रा मोटिफ, पक्षियों से प्रेरित प्रिंट्स और ग्राफिक पैटर्न्स को नए रूप में पेश किया गया।

सत्या पॉल मेन्स वियर ने आधुनिक पुरुषों के लिए एक नई फैशन सोच को सामने रखा। यह कलेक्शन व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और विशिष्ट शैली पर आधारित है। इसमें ट्रैवलर (Traveller) और कलेक्टर (Collector) जैसी प्रिंट कहानियां शामिल हैं।

Created by Universal Document Converter

नेतन्याहू को मैंने जमकर डांटा, खामेनेई से मिलना चाहूंगा

ईरान से बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान संघर्ष पर कई बातें कही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस युद्ध का बड़ा मकसद ये था कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाए और अब तेहरान इस पर मान गया है कि वह न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। उन्होंने इस दावे को नकार दिया कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बहकावे में आकर उन्होंने ईरान पर हमले का आदेश दिया था। हालांकि उन्होंने यह माना कि लेबनान के मुद्दे पर उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाई है।

न्यूयॉर्क पोस्ट का पॉड फोर्स वन पॉडकास्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ईरान में जमीन पर सेना उतारने की जरूरत नहीं है। अमेरिका एयरफोर्स ने बमबारी करके ईरानी सेना को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान बुरी तरह कमजोर हो चुका है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से वह मिलना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी ना किसी मोड़ पर मैं अयातुल्ला से जरूर मिलूंगा और शायद यह हो सके।

डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान कहा कि अगर वह नहीं होते तो आज इजरायल का वजूद भी नहीं होता। ईरान से युद्ध के लिए नेतन्याहू के धोखे पर उन्होंने कहा कि इसकी शुरूआत तो मैंने ही की थी। मैंने इसकी शुरूआत इसलिए की क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दे सकते हैं।

नेतन्याहू को डांटने और पागल बुलाने पर ट्रंप ने कहा कि हां मैंने कहा था। मुझे हमेशा गुस्सा आता है। मैं उनसे नाराज था क्योंकि वह लगातार लेबनान से लड़ रहे थे। आप जानते हैं, एक समय मैंने कहा था कि अब हम इसे रोकेंगे। ऐसे में लेबनान के मुद्दे पर मेरी उनसे कुछ तीखी बात. चीत हो गई।

होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के बारे में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि ये अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। यह मामला काफी जल्दी अपने आप सुलझ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान में अमेरिका को सैन्य तौर पर बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। ईरान के नए नेतृत्व के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने पुष्टि की कि सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई बातचीत में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बातचीत में शामिल हैं। लोग कहते हैं कि वह ही मंजूरी दे रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से ऐसा ही होता आया है।

दाचीगाम आगंतुकों के लिए खुला है, आज कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया: सरकार ने किया स्पष्ट

संवाददाता

श्रीनगर। सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में आगंतुकों के प्रवेश के लिए पूरी तरह से खुला है और आज आम लोगों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

एक आधिकारिक बयान में, सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह स्पष्टीकरण 3 जून, 2026 को दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश पर कथित प्रतिबंधों के संबंध में चल रहे कुछ दावों के जवाब में जारी किया जा रहा है।

प्रवक्ता ने कहा, ष्यह स्पष्ट किया जाता है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में सभी आगंतुक. ों के लिए प्रवेश सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पूरी तरह से खुला है। सरकार द्वारा आज, 3 जून को पार्क में प्रवेश के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।ष

बयान में आगे जनता को सलाह दी गई कि वे बिना पुष्टि वाली रिपोर्टों पर ध्यान न दें और राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के लिए लागू मानक प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रवक्ता ने आगे कहा, ष्जनता को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा के लिए मानक प्रक्रियाओं का पालन करें और बिना पुष्टि वाली खबरों पर ध्यान न दें।

जेएंडके सरकार ने सौरभ भगत को आईटी और जन शिकायत विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा

संवाददाता

जम्मू। जम्मू और कश्मीर सरकार ने बुधवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सौरभ भगत को सूचना प्रौद्योगिकी और जन शिकायत विभाग के प्रशासनिक सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या 1038–जेके(जीएडी) 2026 के अनुसार, सौरभ भगत, आईएएस (एजीएमयूटीरू 2002), जो सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त/सचिव हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और जन शिकायत विभाग के प्रशासनिक सचिव का प्रभार भी संभालेंगे।

आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था प्रशासन के हित में की गई है और अगले आदेश तक लागू रहेगी। यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के आद. ेश पर जारी किया गया था और इस पर सरकार के आयुक्त/सचिव, एम. राजू, आईएएस के हस्ताक्षर हैं। यह आदेश जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधित विभागों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि को मंजूरी दी

नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्धारित भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता प्रदान करने हेतु तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 10,000 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी है।

यह निर्णय पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व अस्थिरता को देखते हुए लिया गया है, जिसके चलते दुनिया भर की विमानन कंपनियों के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इस स्वीकृत व्यवस्था का उद्देश्य भारतीय विमानन कंपनियों के लिए एटीएफ की कीमतों में अधिक स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करना है, साथ ही हवाई सेवाआ. ें की निरंतरता बनाए रखना और यात्रियों को ईंधन की कीमतों में अचानक होने वाले झटकों से बचाना है।

कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए नागरिक विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू ने कहा, ष्प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में सरकार ने यात्रियों, एयरलाइंस और व्यापक विमानन व्यवस्था के हितों की रक्षा के लिए लगातार समयबद्ध और सुनियोजित उपाय किए हैं। इससे पहले, आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत एयरलाइंस के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिससे उन्हें तरलता के लिहाज से जरुरी मदद मिली। आज, मंत्रिमंडल ने एक बार फिर दूरगामी निर्णय लेते हुए एटीएफ की कीमतों को स्थिर करने के लिए ओएमसी को 10,000 करोड़ रुपये की ब्याज–मुक्त सहायता को मंजूरी दी है। इस कदम से ईंधन की लागत में अनिश्चितता कम होगी और एयरलाइंस को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही कम हवाई किराए के चलते हमारे यात्रियों को भी लाभ होगा।ष

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह निर्णय सरकार द्वारा पहले से ही उठाए गए सुनियोजित उपायों की श्रृंखला पर आधारित है। "इस अभूतपूर्व स्थिति की शुरूआत से ही, सरकार ने यात्रियों के हितों की रक्षा करते हुए विमानन क्षेत्र के समर्थन में एक सक्रिय और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। वैश्विक ईंधन बाजारों में देखी गई अत्यधिक वृद्धि के बावजूद, घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ आधार मूल्य में वृद्धि को नियंत्रित किया गया और इसे 25 प्रतिशत तक ही सीमित कर दिया गया। इसके अलावा, घरेलू एयरलाइन्ना. े के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में भी 25 प्रतिशत की कमी की गई। साथ ही, मैं दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों का आभारी हूं कि उन्होंने एटीएफ पर वैट को घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया, जहां से देश के एटीएफ की लगभग 75–80 प्रतिशत खपत होती है।"

सामान्य परिस्थितियों में एटीएफ एयरलाइन परिचालन लागत का लगभग 40 प्रतिशत होता है और ईंधन की कीमतों में अत्यधिक उतार–चढ़ाव के समय यह कुल परिचालन व्यय का 60 प्रतिशत तक हो सकता है। इस तरह के उतार–चढ़ाव एयरलाइन के संच. ालन, मार्ग प्रबंधन और किराए की स्थिरता को काफी हद तक प्रभावित कर सकते है।

एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण सहायता व्यवस्था को दी गई मंजूरी, भारत के विमानन क्षेत्र की मजबूती को बढ़ाने के साथ–साथ बेहतर संपर्क, आर्थिक विकास और उड़ान में सुगमता के जरिए, विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

इस निर्णय के प्रभाव को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, व्यापार और निर्यात जैसे अन्य क्षेत्रों पर इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए विमानन उद्योग और अन्य क्षेत्रों ने इस निर्णय की सराहना की है। इससे हम हवाई संचालन में निरंतरता सुनिश्चित कर सकेंगे, जिससे यात्रियों के साथ–साथ उच्च मूल्य वाले हवाई माल की आवाजाही भी सुगम होगी।"

एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण सहायता व्यवस्था 36 महीनों तक वार्षिक समीक्षा के प्रावधान के साथ या अग्रिम राशि की पूर्ण वसूली और निपटान होने तक, जो भी पहले हो, तब तक लागू रहेगी। नागरिक विमानन मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और व्यय विभाग के प्रतिनिधियों वाली एक निगरानी समिति कार्यान्वयन, दावों के सत्यापन, मिलान और निपटान प्रक्रिया की देखरेख करेगी।

नागरिक विमानन मंत्रालय वर्तमान स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और मौजूदा संकट से उत्पन्न परिचालन चुनौतियों का आकलन करने के लिए एयरलाइनों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क में है।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने पश्चिम एशिया संकट के संभावित प्रभाव से एमएसएमई को बचाने के उपायों की समीक्षा की

श्री मांझी ने बदलती हुई स्थिति पर बारीकी से नजर रखने और वैश्विक घटनाक्रमों से उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समयबद्ध और उपयुक्त रणनीति विकसित करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी और एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने 2 जून, 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च–स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया के भू–राजनीतिक घटनाक्रमों का भारत के एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना था।

इस बैठक में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, निर्यात और आयात, गैस से संबंधित मुद्दों, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, तथा एमएसएमई क्षेत्र के कार्यशील पूंजी संबंधी मामलों के कारण कच्चे माल की उपलब्धता और कीमतों की व्यापक समीक्षा की गई। मंत्री महोदय ने बदलती हुई स्थिति पर बारीकी से नजर रखने और वैश्विक घटनाक्रमों से उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समयबद्ध और उपयुक्त रणनीति विकसित करने का निर्देश दिया।

बैठक को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने भारत की आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र न केवल लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है, बल्कि देश के विनिर्माण, उत्पादन और निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने एमएसएमई उद्यमियों के हिता. ें की रक्षा करने और इस क्षेत्र के निरंतर विकास तथा सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया।

श्री मांझी ने इस बात पर भी जोर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आत्मनिर्भर भारत और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएसई), डिजिटल सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन जैसी पहलों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की सुदृढ़ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत किया है।

जम्मू में भाजपा तेजी से अपना राजनीतिक आधार खो रही है: रतन लाल गुप्ता

कहा–भाजपा की जन–विरोधी नीतियों ने समाज के हर वर्ग को निराश किया है

संवाददाता

जम्मू। जम्मू और कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि भाजपा जम्मू में तेजी से अपना राजनीतिक आधार खो रही है क्योंकि वह लोगा. े से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। बेरा. ेजगारी, महंगाई, खराब होते बुनियादी ढांचे, जरूरी सेवाओं की कमी और जम्मू–कश्मीर को राज्य का दर्जा न दिए जाने जैसे गंभीर सार्वजनिक मुद्दों को सुलझाने के बजाय भाजपा नेता लोगों का ध्यान गैर–जरूरी मुद्दों की ओर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

जानीपुर कालोनी जम्मू में एक सार्वजनिक लंगर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही। इस सार्वजनिक लंगर का आयोजन सरदार गुरनाम सिंह (जि"ला सचिव जम्मू शहरी), पुष्प जंडियाल और केवल शर्मा ने किया था। इस मौके पर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि जम्मू के लोग पिछले कई

सालों में भाजपा के खराब प्रदर्शन से पूरी तरह वाकिफ हैं। अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहने और मतदाताओं के सामने अपने काम का हिसाब देने में असमर्थ होने के कारण स्थानीय भाजपा नेताओं ने मतदाताओं के सामने माफी मांगने वाला रवैया अपना लिया है। आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों से राजनीतिक चर्चा को दूर ले जाने की उनकी बार–बार की कोशिशें, उनकी घबराहट और जनता से बढ़ते अलगाव को साफ तौर पर दिखाती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा की नीतियों ने समाज के हर वर्ग को निराश किया है जिसमें युवा, किसान, व्यापारी, कर्मचारी और कमजा. ेर वर्ग शामिल हैं। लोगों को विकास, रोजगार के अवसर, आर्थिक विकास और लो. कतांत्रिक अधिकारों की बहाली की उम्मीद थी लेकिन इसके बजाय उन्हें अधूरे वादे और बढ़ती मुश्किलें ही मिली हैं। गुप्ता ने कहा कि जम्मू प्रांत भर में लोगों की बढ़ती नारा. जगी साफ दिखाई दे रही है। भाजपा नेतृत्व को अब मतदाताओं का सामना करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि लोग पार्टी की नाक. ामियों के लिए जवाबदेही मांग रहे हैं। ध्यान भटकाने और गैर–जरूरी विवाद खड़े करने की उनकी हताश कोशिशें उनके खराब शासन और टूटे वादों की असलियत को छिपा नहीं सकतीं। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस लोगों के हिता. े की रक्षा करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

एसएमवीडीयू में एनसीसी कैडेट्स के लिए स्कीट शूटिंग प्रैक्टिस सेशन आयोजित

संवाददाता

जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में ऐयर एनसीसी के तत्वावधान में एनसीसी कैडेट्स के लिए स्कीट शूटिंग प्रैक्टिस सेशन की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इन सेशन ने कैडेट्स को स्कीट शूटिंग के खेल का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और शूटिंग के जरूरी कौशल विकसित करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया।

इन प्रैक्टिस सेशन में एनसीसी कैडेट्स ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और उन्होंने टारगेट शूटिंग के मूल सिद्धांत, सुरक्षा प्रक्रियाएं और सटीक शूटिंग के लिए आवश्यक तकनीकें सीखीं। स्कीट शूटिंग के लिए उच्च स्तर की एकाग्रता, सटीकता, तालमेल और त्वरित प्रतिक्रियाओं की

आवश्यकता होती है जो इसे कैडेट्स के बीच अनुशासन और मानसिक सतर्कता विक. सित करने के लिए एक आदर्श गतिविधि बनाती है। इन कई प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से कैडेट्स उचित पर्यवेक्षण के तहत अपनी शूटिंग क्षमताओं में धीरे–धीरे सुधार करने और शूटिंग उपकरणों को संभालने में आत्मविश्वास विकसित करने में सक्षम हुए।

इस पहल ने कैडेट्स को प्रतिस्पर्धी शूटिंग खेलों में अवसरों का पता लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। स्कीट शूटिंग ओलंपिक खेलों में मान्यता प्राप्त शूटिंग विधाओं में से एक है और इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विशिष्ट खिलाड़ियों को जन्म दिया है। ये सेशन कैडेट्स के लिए एक ओलंपिक खेल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में कार्य करते हैं और कई कैडेट्स को शूटिंग तथा अन्य खेल गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। कैडेट्स ने इस अवसर के लिए अपनी सराहना व्यक्त की और इन सेशन को शैक्षिक और प्रेरक दोनों बताया जिन्होंने उनके समग्र विकास और खेल भावना में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मालवीय नगर अग्निकांड पर खरगे–प्रियंका ने जताया शोक

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई विपक्षी नेताओं ने मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख जताया है। खरगे और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस समर्थकों से अपील की कि वे इस कठिन समय में पीड़ितों को हर संभव मदद और सहयोग प्रदान करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा कि दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की दुखद घटना से मैं बेहद आहत हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।

खरगे ने मांग की कि राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों को पर्याप्त और समय पर मुआवजा देना चाहिए, जिसमें तत्काल मेडिकल सहायता भी शामिल हो। इसके साथ ही, उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे इस कठिन समय में पीड़ितों को हर संभव मदद और सहयोग प्रदान करें।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट किया कि मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु और करीब तीन दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोकसंतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। कांग्रेस के साथियों से मेरी अपील है कि कृपया प्रभावित लोगों की यथासंभव मदद करें।

मंगलूर में जन शिकायत शिविर–डीसी ने दिए समस्याओं के समयबद्ध समाधान के निर्देश

संवाददाता

कठुआ। डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने बुधवार को ब्लॉक डिंगा अंब के पंचायत मंगलूर ईस्ट में जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और जनसेवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याएं उठाईं।

डीसी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सप्ताह में एक–दो बार फील्ड विजिट कर विकास कार्यों की निगरानी और जनता से सीधा संवाद बनाए रखने को भी कहा। खेल मैदान की मांग पर उपायुक्त ने बताया कि मामला पहले ही स्पोर्ट्स काउंसिल के समक्ष उठाया जा चुका है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि आगामी बुधवार को ब्लॉक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से जिला प्रशासन के "100–दिवसीय नशा मुक्त अभियान" में सक्रिय सहयोग देने की अपील करते हुए युवाओं को नशे से दूर रखने का आह्वान किया। अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि शि. विर में उठाई गई सभी जायज समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर एडीसी कठुआ महिमा मदान, एसडीएम हीरानगर फुलेल सिंह, सीपीओ रंजीत ठाकुर सहित कई जिला अधिकारी मौजूद रहे।

उधमपुर में 5 दिवसीय शांति शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन

संवाददाता

उधमपुर (संजीव शर्मा)। प्रेम रावत फाउंडेशन द्वारा उधमपुर

जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित पांच दिवसीय शांति शिक्षा कार्यक्रम का आज यहां समापन हो गया।

जिला प्रशासन के अधिका. रियों और कर्मचारियों ने व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित संवादात्मक सत्रों की श्रृंखला में सक्रिय रूप से भाग लिया।

अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त जुगल किशोर समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

एडीडीसी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में प्रेम रावत फाउंडेशन के समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रतिभागियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और शांतिपूर्ण कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने आत्म–जागरूकता, भावनात्मक संतुलन, गरिमा और आपसी समझ को बढ़ाने में ऐसे कार्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रेम रावत फाउंडेशन की फैसिलिटेटर पूनम शेरावत ने अपनी टीम के साथ सत्रों का संचालन किया और इस बात पर जोर दिया कि शांति एक आंतरिक संसाधन है जिसे चिंतन, आत्म समझ और जागरूकता के माध्यम से पोषित किया जा सकता है।

Created by Universal Document Converter

राहुल की नई कांग्रेसरू कर्नाटक में आसान सत्ता बदलाव से 2029 का रोडमैप तैयार!

ओंकारेश्वर पांडेय

कर्नाटक में सिद्धारमैया के इस्तीफे और डीके शिवकुमार की ताजपोशी के जरिए राहुल गांधी ने कांग्रेस में गुटबाजी के युग को खत्म कर दिया! वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडेय का विश्लेषण पढ़िए, राहुल गांधी ने कैसे दिया कांग्रेस को अनुशासन का नया खाका।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक पल में, कर्नाटक का लंबा सियासी नाटक किसी विस्फोट में नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हस्तांतरण के साथ समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 28 मई, 2026 को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया, जिससे डी.के. शिवकुमार दृ वोक्कालिगा के दमदार नेता और पार्टी के श्अंतिम समाधानकर्ताश दृ के लिए रास्ता साफ हो गया। वह 3 जून को बेंगलुरु के ग्लास हाउस में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

लेकिन यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। राहुल गांधी द्वारा बारीकी से लिखा गया यह परिवर्तन पार्टी के संघीय ढांचे में एक स्पष्ट संदेश भेजता हैरू क्षेत्रीय द्वंद्वों, टूटे वादों और नेतृत्व की ठप्पता का युग खत्म हुआ। आंतरिक समझौतों का सम्मान होगा। समयसीमा लागू होगी। और जो लोग सामूहिक हित को नुकसान पहुँचाएंगे दृ जिनमें कांग्रेस के भीतर मौजूद श्भाजपा के मोलश शामिल हैं दृ उन्हें अंजाम भुगतना होगा। जिसे व्यापक रूप से 2029 के आम चुनाव के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा जा रहा है, उसमें हाई कमान ने रेत में एक स्पष्ट रेखा खींच दी है।

कांग्रेस को आंतरिक कलह का नुकसान

कांग्रेस पार्टी का हालिया इतिहास उन हारों से भरा पड़ा है जो चुनावी पराजय से नहीं, बल्कि आत्मघाती आंतरिक कलह से हुई हैं। कर्नाटक भी लगभग उसी दुखद सूची में शामिल हो गया था, और नेतृत्व ने अपनी नई निर्दयता को सही ठहराने के लिए पिछली विफलताओं के भूतों को आमंत्रित किया है।

राजस्थान में, अशोक गहला. ेत और सचिन पायलट के बीच पाँच साल के लंबे गृह युद्ध ने जनता का विश्वास खो दिया, जिससे भाजपा ने 115 सीटों पर कब्जा कर लिया जबकि कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनावों में महज 69 पर सिमट गई। विश्लेषकों ने कहा कि जुलाई 2020 में चरम पर पहुँचे इस झगड़े ने पार्टी के शासन और कथा को घातक रूप से कमजोर कर दिया।

छत्तीसगढ़ में, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके डिप्टी टी.एस. सिंह देव के बीच गहरी दरार ने सीधे पार्टी की चौंकाने वाली हार में योगदान दिया। सिंह देव ने खुद माना कि दोनों नेताओं के बीच श्एक साथ बैठनेश में असमर्थता और श्आंतरिक मुद्देश हार का एक कारण हो सकते हैं।

पंजाब में, हाई कमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विद्रोह करवाया, उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया।

पंजाब में इस श्गृह युद्धश ने मतदाताओं को निराश कर दिया और राज्य ऐतिहासिक रूप से आम आदमी पार्टी के हाथों में चला गया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बाद में माना कि इस कलह ने विपक्ष को वह जीत दे दी जो कांग्रेस अन्यथा हासिल कर सकती थी।

हरियाणा में, हुड्डा–सेलजा की कड़वी दरार 2024 के विधानसभा चुनावों में विनाशकारी साबित हुई। हुड्डा खेमे ने लगभग 70 टिकट हासिल किए, जबकि सेलजा खेमा मात्र नौ पर सिमट गया, और दलित नेता ने दो सप्ताह तक प्रचार से भी दूरी बनाए रखी। इस आंतरिक कलह ने सीधे उस सरकार को खो दिया जिसे पार्टी जीतने की उम्मीद कर रही थी।

असम में, 2021 के विधानसभा चुनावों में आंतरिक कलह और गठबंधन की कमजोर रणनीति को हार के प्रमुख कारणों के रूप में देखा गया, जहाँ कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 126 सदस्यीय सदन में भाजपा के 75 के मुकाबले मात्र 50 सीटें ही हासिल कर सका। केरल में भी, जबकि 2026 में यूडीएफ ने वापसी की, कांग्रेस जिला और स्थानीय स्तरों पर गहरे गुटबाजी के तनाव से जूझ रही है।

हाई कमान का संदेश साफ है: पार्टी अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी अध्यक्ष और हाई कमान के प्रति निष्ठा गैर–संवेदनशील है। केंद्रीय अधिकार को चुनौती देने वालों को अब जगह नहीं मिलेगी, और क्षेत्रीय दिग्गजों द्वारा पार्टी को बंधक बनाने के दिन खत्म हुए। श्भाजपा के मोलश और जो व्यक्तिगत लाभ के लिए आंतरिक तोड़फोड़ करेंगे, उनकी पहचान की जाएगी, उन्हें किनारे लगाया जाएगा और बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

अतीत की अराजकता के बिल्कुल विपरीत, कर्नाटक का परिवर्तन संस्थागत वार्ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 2023 की निर्णायक जीत के बाद की गई 50रू50 सत्ता–साझाकरण की समझौते का पूरी तरह से सम्मान किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, हाई कमान ने नए मंत्रिमंडल को श्राजनीतिक रूप से संतुलितश बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें दलितों, पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों को बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, साथ ही 60 वर्ष से कम उम्र के युवा चेहरों को शामिल किया जाएगा।

24/7 मीडिया कवरेज के इस युग में, राहुल गांधी की टीम ने कोई मौका नहीं छोड़ादृ सिद्धारमैया के अपने मंत्रिमंडल के साथ नाश्ते की बैठक से लेकर शिवकुमार द्वारा अपने पूर्ववर्ती के पैर छूकर आशीर्वाद लेने तक, हर कदम को अधिकतम प्रभाव के लिए कोरियोग्राफ किया गया।

कर्नाटक एक मिसाल

नेतृत्व उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने जमीनी कार्य और निष्ठा के साथ इसे अर्जित किया है। डी.के. शिवकुमार, जिन्होंने 50 दिन तिहाड़ जेल में बिताए, जिन्होंने अहमद पटेल की राज्यसभा जीत के लिए गुजरात के विधायकों को सुरक्षित रखा, और जिन्होंने भाजपा को ध्वस्त करने वाला श्पे–सीएमश अभियान चलाया, आज इसलिए ऊपर उठाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसे अर्जित किया। जो लोग आंत. रिक कलह करेंगे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पार्टी से ऊपर रखेंगे, या छुपकर भाजपा के लिए काम करेंगे, उन्हें कोई जगह नहीं मिलेगी।

पे–सीएम अभियान सितंबर 2022 में कर्नाटक कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक अत्यधिक आक्रामक, वायरल राजनीतिक गुरिल्ला मार्केटिंग अभियान था। इसे मई 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले तत्कालीन सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की छवि को मौलिक रूप से नुकसान पहुँचाने वाली सबसे प्रभावी कथा–निर्माण रणनीतियों में से एक माना जाता है। यह अभियान डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया के नेतृत्व में तैयार और संचालित किया गया था।

विधानसभा चुनाव और 2029 की लड़ाई

अगले साल कई राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, और 2029 का हाई–स्टेक आम चुनान अब पूरी तरह फोकस में है, कांग्रेस एक लंबे, अनुशासित अभियान के लिए खुद को तैयार कर रही है। कर्नाटक ब्लूप्रिंट को राष्ट्रीय टेम्पलेट के रूप में स्थापित किया जा रहा है। जहां आलोचक सिद्धारमैया के विशाल ओबीसी और अहिंदा समर्थन आधार को अलग करने के जोखिम की ओर इशारा करते हैं, वहीं हाई कमान आश्वस्त है कि एक संतुलित मंत्रिमंडल दृ जिसम. े दो उपमुख्यमंत्री, जिसमें एक दलित नेता शामिल हो सकते हैं दृ इस प्रभाव को कम कर देगा।

राहुल गांधी के लिए यह संदेश अत्यंत व्यक्तिगत है। वर्षों तक एक अनिच्छुक और अनिर्णायक नेता के रूप में चित्रित किए जाने के बाद, उन्होंने अब साबित कर दिया है कि उनके पास राज्य इकाइयों को तोड़े बिना कठोर राजनीतिक परिवर्तनों को लागू करने की संरचनात्मक शक्ति है। श्बेंगलुरु ब्लूप्रिंटश केवल कर्नाटक के लिए एक समाधान नहीं हैय यह पूरी पार्टी के लिए इरादे की घोषणा है।

संदेश साफ है: अब और राजस्थान नहीं। अब और छत्तीसगढ़ नहीं। अब और पंजाब नहीं। आंतरिक कलह का युग समाप्त। अनुशासन लागू होगा। नेतृत्व उन्हीं का है जो इसके लिए काम करें। और कांग्रेस आखिरकार जीतने के लिए गंभीर हो गई है।

ट्रंप और नेतन्याहू की नीतियों से परेशान दुनिया

लेबनान पर इजरायल के हमले ने पश्चिम एशिया में हालात और बिगाड़ दिए हैं। इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के बढ़ते युद्धोन्माद को अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सही ठहराते आए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने भस्मासुर खड़ा करके अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। हम नहीं जानते कि ट्रंप ने भस्मासुर जैसी कोई कहानी कभी सुनी है या नहीं, लेकिन अपने लंबे जीवन अनुभव से उन्होंने इतना तो सीखा ही होगा कि बुराई का फल बुराई के रूप में ही वापस मिलता है। दरअसल लेबनान पर इजरायल के हमले रुक ही नहीं रहे हैं, हाल ही में इजरायल ने लेबनान के दहिये और बेरूत पर बमबारी करने की धमकी दी है और वहां के निवासियों के लिए इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की है। इस पर ईरान ने भी कहा है कि इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, साथ ही इजरायल के उत्तरी इलाके पर पलटवार करने का इरादा जताते हुए वहां के निवासियों को बचने के लिए सुरक्षित स्थान जाने की सलाह दी है। ईरान ने अमेरिका से जब पहली बार अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति दी थी तो उसकी शर्तों में लेबनान पर इजरायल के हमले रो. कना भी शामिल था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, इस पर अब डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा है। सोमवार को खबर आई कि ट्रंप ने फोन कॉल पर ही नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाई और यहां तक कह दिया कि, श्तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज की तारीख में हर कोई तुमसे नफरत करता है।श बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने इजरायल को लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन और हवाई हमलों को तुरंत रोकने के लिए कड़ा दबाव बनाया। जिसके बाद इजरायल बेरूत में अपने सैन्य कदम रोकने के लिए राजी हुआ है।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नेतन्याहू पर किस किस्म का दबाव ट्रंप बना सकते हैं, क्योंकि दावा तो यही है कि नेतन्याहू एपस्टीन फाइल्स के नाम पर ट्रंप को दबाव में रखे हुए हैं। हालांकि नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधी है, और उन के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, कई देशों में उनके जाने पर प्रतिबंध है, तो मुमकिन है ट्रंप ने उन पर ऐसा ही कोई दबाव बनाया हो। बता दें कि नेतन्याहू को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 21 नवंबर 2024 को युद्ध अपराधी घोषित कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन वारंट्स में उन पर गजा में युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी का उपयोग करने और नागरिकों पर जानबूझ कर हमले करने जैसे युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप लगाए गए हैं।

तबाही की तरफ धकेल दिया है। ईरान पर अमे. रिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान को मजबूरन होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग बंद करना पड़ा, ताकि दुनिया में तेल की आपूर्ति बाधित हो तो इन दोनों देशों को युद्ध की कीमत चुकाने का अहसास हो। हालांकि वेनेजुएला के तेलस्रोतों पर कब्जा करके या रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाकर अमेरिका अब तक अपनी दादागिरी को चला रहा है। लेकिन अब उसकी जिद भी कहीं न कहीं टूट रही है। ट्रंप जाहिर तौर पर तो ईरान के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कभी अस्थायी युद्धविराम, इस्लामाबाद शांति वार्ता आदि के अलावा अन्य तरीकों से भी समझौतों की कोशिश में लगे हैं। ईरान पर युद्ध में अमेरिका को जितना आर्थिक और सामरिक नुकसान हुआ है, उससे अपने ही देश में ट्रंप घिर चुके हैं। ऐसे में इजरायल की बेवजह आक्रामकता से ईरान के साथ क्षेत्रीय शांति स्थापित करने की अमेरिका की पूरी कूटनीति दांव पर लग गई है, यह ट्रंप समझ रहे हैं। लेबनान पर इजरायल के हमलों के विरोध में ईरान ने ओमान और अन्य माध्यमों से अमे. रिका के साथ चल रही अपनी परोक्ष शांति वार्ता को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़ी मीडिया एजेंसी श्तस्नीमश ने साफ किया है कि जब तक लेबनान और गजा में इजरायल के हमले पूरी तरह नहीं रुकते और ईरान के सहयोगियों के हितों की रक्षा नहीं होती, तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने दो टूक कहा है कि – श्एक मोर्चे पर युद्धविराम का उल्लंघन, सभी मोर्चों पर युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा।श

इसके अलावा ईरान अपने सहयोगी यमन के हूती समूह के जरिए बाब अल–मंदाब समुद्री रास्ते को भी बंद करने की चेता. वनी दी है। होर्मुज के बाद अगर बाब अल–मंदाब भी बंद हुआ तो दुनिया अकल्पनीय नुकसान में पड़ जाएगी। यमन (एशिया) और जिबूती–इरिट्रिया (अफ्रीका) के बीच स्थित यह जलमार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और आगे स्वेज नहर तक जाता है। इस संकरे रास्ते से दुनिया के कुल समुद्री व्यापार के करीब 30 प्रतिशत कंटेनर ट्रैफिक गुजरते हैं। खाड़ी देशों से यूरोप और अमे. रिका जाने वाला रोजाना 40 से 70 लाख बैरल कच्चा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी मार्ग से भेजा जाता है। अगर ईरान और हूती ने इस रास्ते को बाधित कर दिया, तो जहाजों को अफ्रीका के श्केप ऑफ गुड होपश से घूमकर जाना पड़ेगा। इससे यात्रा का समय 10 से 14 दिन बढ़ जाएगा, माल ढुलाई और इंश्योरेंस का खर्च बेतहाशा बढ़ेगा और पूरी दुनिया में भयानक महंगाई आ जाएगी।

इस वक्त वैसे ही ऊर्जा का वैश्विक संकट कायम है, जिससे त्राहि–त्राहि मची है। अब बाब अल–मंदाब भी अगर बाधित होता है तो तय है कि इजरायल और अमे. रिका के कारण केवल पश्चिम एशिया में तबाही नहीं मचेगी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें और सबसे बढ़कर अहम समुद्री मार्ग पूरी तरह तहस–नहस हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की नेतन्याहू को दी गई चेतावनी इसी आने वाली बड़ी तबाही का डर है।

अमेरिका और इजरायल की आक्रामक नीतियों और कार्रवाइयों पर रूस, चीन के साथ यूरोप, अफ्रीका के कई देश आलोचना कर रहे हैं और ईरान के साथ शांति वार्ता कामयाब होने के पक्षधर हैं। लेकिन भारत इस मामले में अपना स्पष्ट रुख रखने में बार–बार कतरा रहा है। खासकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नरेन्द्र मोदी की नजदीकियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे संकेत नहीं दे रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सही सवाल किया है कि– दुनिया के कई देश इजरायल की इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी वास्तविक श्मातृभूमिश (भारत) से ज्यादा उनकी तथाकथित श्पितृभूमिश (फादरलैंड) मायने रखती है?श आज नहीं तो कल नरेन्द्र मोदी को इसका जवाब देना होगा।

गांव लालेयाल में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई चुन्न बिरादरी की अर्धवार्षिक मेल

संवाददाता

आरएस पुरा। चुन्न बिराद. री की अर्धवार्षिक मेल बुधवार को गांव लालेयाल स्थित कुल देवस्थान पर श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई गई।कुल देवस्थान पर सुबह बिरादरी के लोगों की तरफ से जहां हवन करने का आयोजन किया गया विशाल भंडारा खोला गया जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। बिरादरी की मेल में जम्मू कश्मीर के साथ–साथ पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से भी बिरादरी के लोगों ने परिवार सहित कुलदेव के स्थान पर पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर बिरादरी द्वारा

गठित कमेटी के सदस्य भाना चौधरी, अशोक चौधरी, कमल चौधरी, दर्शन चौधरी, रमेश चौधरी, प्रदीप चौधरी, रामदास बिरादरी के अन्य लोगों ने बताया कि चुन्न बिरादरी की अर्धवार्षिक मेल तरीके के साथ मनाई गई है जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ–साथ पड़ोसी राज्य पंजाब तथा हरियाणा के लोगों ने दी परिवार सहित पहुंचकर हाजिरी लगाई है। उन्होंने कहा कि देवस्थान पर सुबह हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें बिरादरी तथा देश के कल्याण की कामना की गई है और उसके उपरांत विशेष पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारा खोला गया। उन्होंने बताया कि बिरादरी का देवस्थान एक प्राचीन देवस्थान के रूप में जाना जाता है जहां पर अन्य बिरादरी के लोग भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचते है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले बिरादरी के लोगों के लिए गठित कमेटी की तरफ से पूरा प्रबंध किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिरादरी के जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई थी वो बैंड बाजा के साथ देवस्थान पर पहुंचे। इस मौके पर बिरादरी के सुनील चौधरी, रमेश चौधरी, अशोक चौधरी के साथ–साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

Created by Universal Document Converter

भाजपा ओबीसी मोर्चा ने महानपुर मंडल में मासिक संगठनात्मक बैठक आयोजित की, जमीनी स्तर पर पार्टी गतिविधियों की समीक्षा की

जम्मू। भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा महानपुर मंडल में मासिक संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करना तथा मोर्चा के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक सशक्त बनाना था।

बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा विभिन्न संगठनात्मक एवं जनसंपर्क गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की।

इस अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा, पहाड़ी जिला बसोहली–बनी–बिलावर के जिला अध्यक्ष धरम चंद मलगोत्रा ने संगठन को मजबूत करने तथा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जन–जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में उनके योगदान के लिए नीता देवी, मंडल अध्यक्ष, भाजपा ओबीसी मोर्चा, महानपुर मंडल को सम्मानित किया।

बैठक में भाजपा ओबीसी मोर्चा, पहाड़ी जिला बसोहली–बनी–बिलावर के जिला उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त जेडईओ मोहन लाल वर्मा जी तथा भाजपा

महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष एवं बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान की भाजपा जिला सह–प्रभारी सुलेक्खा शर्मा जी भी उपस्थित रहीं।

दोनों नेताओं ने मोर्चा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए बूथ, मंडल एवं जिला स्तर पर मजबूत समन्वय बनाए रखने के महत्व पर बल दिया।

बैठक के दौरान मंडल स्तर पर भाजपा की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा एवं विश्लेषण किया गया। चर्चा का मुख्य केंद्र संगठनात्मक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाना, जनसंपर्क कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, पार्टी गतिविधियों में ओबीसी समुदाय की भागीदारी बढ़ाना तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना रहा।

अपने संदेश में भाजपा ओबीसी मोर्चा, जम्मू–कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्म ज्योत सत्ती ने महानपुर मंडल इकाई द्वारा नियमित रूप से संगठनात्मक बैठकों के आयोजन तथा जमीनी स्तर पर पार्टी को सशक्त बनाने के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि भाजपा ओबीसी मोर्चा ओबीसी समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा, उपलब्धियों एवं जनहितकारी कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मंडल स्तर पर मजबूत संगठनात्मक ढांचा अत्यंत आवश्यक है।

सत्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनता के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने, बूथ स्तर की समितियों को मजबूत करने तथा समाज के सभी वर्गों तक पार्टी की पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए समर्पण एवं निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

वक्ताओं ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने, उनकी समस्याओं को सुनने तथा विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने का आग्रह किया।

सभा को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखने तथा पार्टी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए नियमित संगठनात्मक बैठकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भाजपा को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने के लिए पूर्ण समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

वेदों के स्वाध्याय और यज्ञ से मिलता है निरोग जीवन व दीर्घायु: स्वामी राम स्वरूप जी

कठुआ। वेद मन्दिर योल में चल रहे 78 दिवसीय चारों वेदों के यज्ञानुष्ठान के 53वें दिन स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य ने अथर्ववेद काण्ड 3 सूक्त 10 एवं 11 के आधार पर श्रद्धालुओं को ज्ञान प्रदान किया।

स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य जन्म पाकर हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विद्वानों से वेदों को सुने और उनका नियमित स्वाध्याय करे, तभी वह सच्चे अर्थों में तपस्वी कहलाने योग्य बनता है। उन्होंने बताया कि वेदों के अनुसार तप, स्वाध्याय और साधना से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे विकारों का नाश होता है और जीवन पवित्र बनता है। स्वामी जी ने आगे कहा कि नित्य अग्निहोत्र, यज्ञ, ईश्वर में आस्था और नाम–सिमरन से व्यक्ति को निरोगता और दीर्घायु प्राप्त होती है। उन्होंने अथर्ववेद का उल्लेख करते हुए कहा कि परमेश्वर स्वयं वचन देता है कि साधक को गंभीर रोग और मृत्यु के मुख से भी वापस लाकर सौ वर्ष तक स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि वर्तमान समय में लोग वेदों से दूर हो गए हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव, रोग और अल्पायु जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि भारत को पुनः महान बनाने और जीवन को सुखमय बनाने के लिए वेद मार्ग को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

गांव लालेयाल में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई चुन्न बिरादरी की अर्धवार्षिक मेल

आरएस पुरा। चुन्न बिरादरी की अर्धवार्षिक मेल बुधवार को गांव लालेयाल स्थित कुल देवस्थान पर श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई गई।कुल

देवस्थान पर सुबह बिरादरी के लोगों की तरफ से जहां हवन करने का आयोजन किया गया विशाल भंडारा खोला गया जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। बिरादरी की मेल में जम्मू कश्मीर के साथ–साथ पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से भी बिरादरी के लोगों ने परिवार सहित कुलदेव के स्थान पर पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर बिरादरी द्वारा गठित कमेटी के सदस्य भाना चौधरी, अशोक चौधरी, कमल चौधरी, दर्शन चौधरी, रमेश चौधरी, प्रदीप चौधरी, रामदास बिरादरी के अन्य लोगों ने बताया कि चुन्न बिरादरी की अर्धवार्षिक मेल तरीके के साथ मनाई गई है जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ–साथ पड़ोसी राज्य पंजाब तथा हरियाणा के लोगों ने दी परिवार सहित पहुंचकर हाजिरी लगाई है। उन्होंने कहा कि देवस्थान पर सुबह हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें बिरादरी तथा देश के कल्याण की कामना की गई है और उसके उपरांत विशेष पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारा खोला गया। उन्होंने बताया कि बिरादरी का देवस्थान एक प्राचीन देवस्थान के रूप में जाना जाता है जहां पर अन्य बिरादरी के लोग भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले बिरादरी के लोगों के लिए गठित कमेटी की तरफ से पूरा प्रबंध किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिरादरी के जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई थी वो बैंड बाजा के साथ देवस्थान पर पहुंचे। इस मौके पर बिरादरी के सुनील चौधरी, रमेश चौधरी, अशोक चौधरी के साथ–साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

'मातृ स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कार्रवाई का आग्रह'

सी–सेक्शन में बेरोकटोक बढ़ोतरी चिंताजनक: रमन सूरी

जम्मू। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रमन सूरी ने जम्मू और कश्मीर में सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी की लगातार बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस रुझान को चिंताजनक बताया है और कहा है कि स्वास्थ्य अधिकारियों को इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उन रिपोर्टों का हवाला देते हुए जिनमें सरकारी और निजी, दोनों तरह के अस्पतालों में सर्जिकल डिलीवरी में तेजी से बढ़ोतरी का संकेत मिला है, सूरी ने कहा कि जहां जटिल मामलों में मां और नवजात शिशु की जान बचाने के लिए अक्सर सी–सेक्शन जरूरी होता है वहीं सामान्य गर्भधारण में इसकी बढ़ती व्यापकता की गहन जांच की जानी चाहिए।

सूरी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में किए गए स्वास्थ्य डेटा और सर्वेक्षणों से शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में सीजेरियन डिलीवरी में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि यह रुझान अब केवल निजी स्वास्थ्य संस्थानों तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि सरकारी अस्पतालों में भी यह तेजी से आम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति मातृ स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं, जागरूकता के स्तर, जीवनशैली में बदलाव और प्रसव के दौरान सर्जिकल हस्तक्षेप पर बढ़ती निर्भरता में योगदान देने वाले अन्य कारकों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है।

तत्काल कार्रवाई का आह्वान करते हुए रमन सूरी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से आग्रह किया कि वे केंद्र शासित प्रदेश में सी–सेक्शन डिलीवरी की बढ़ती संख्या के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए एक गहन और वैज्ञानिक अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि विभाग को जि"ला–वार डेटा एकत्र और विश्लेषण करना चाहिए, इस रुझान के लिए जि"म्मेदार चिकित्सा, पोषण, जीवनशैली और संस्थागत कारकों की पहचान करनी चाहिए और एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से

हल करने के लिए साक्ष्य–आधारित नीतिगत निर्णय लिए जा सकें। वरिष्ठ भाजपा नेता ने इस बात पर जोर दिया कि जहां भी चिकित्सकीय रूप से संभव हो सामान्य डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपायों को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रस्तावित अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर स्वास्थ्य अधिकारियों को गर्भवती महिलाओं के लिए विशिष्ट आहार संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए, नियमित पोषण परामर्श प्रदान करना चाहिए और गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों की आवश्यकता है जो गर्भवती माताओं को सुरक्षित शारीरिक गतिविधियों, प्रसव–पूर्व व्यायाम और अन्य वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीकों के बारे में मार्गदर्शन दे सकें जिससे मातृ स्वास्थ्य में सुधार हो और सामान्य प्रसव की संभावना बढ़े।

सूरी ने कहा कि अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए ताकि महिलाओं और उनके परिवारों को गर्भावस्था की देखभाल, पोषण और सामान्य डिलीवरी के लाभों के बारे में शिक्षित किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि गर्भवती माताओं को डिलीवरी के विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और सिजेरियन सेक्शन का विकल्प चुनने से पहले सामान्य प्रसव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए सिवाय उन मामलों के जहां मां या बच्चे की सुरक्षा के लिए सर्जरी चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो। इस बात को दोहराते हुए कि मां और बच्चे का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता बना रहना चाहिए रमन सूरी ने डाक्टरों, स्वास्थ्य संस्थानों और नीति निमार्ताओं से आह्वान किया कि वे बेहतर निगरानी, परामर्श, पोषण सहायता और निवारक स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से टाली जा सकने वाली सर्जिकल डिलीवरी को कम करने की दिशा में मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि एक संतुलित और रोगी–केंद्रित दृष्टिकोण न केवल मां और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करेगा बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ाने में भी मदद करेगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि सिजेरियन सेक्शन केवल वास्तविक चिकित्सकीय आधार पर ही किए जाएं।

Printer, Publisher, Owner, Editor by: Sanktha Prasad Singh Published from: GH Road Skara, Near Ladakh Public School, Leh (Ladakh) - 194104, Published from: Ladakh Imperial Printing press, Gh Skara, Near Ladakh Public School, Leh Ladakh, 194104, Mob.: Mob.: 9818069272, 8287390112, Email: ladakhtoday@gmail.com
**All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts and forums in Leh - city.

Created by Universal Document Converter